

## अर्थव्यवस्था की स्थिति

वर्ष 2019 वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक कठिन वर्ष था जहां वर्ष 2009 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद विश्व की उत्पादन वृद्धि दर 2.9 प्रतिशत की अपनी सबसे मंद गति पर प्राक्कलित की गई जोकि वर्ष 2018 में 3.6 प्रतिशत और वर्ष 2017 में 3.8 प्रतिशत की नियंत्रित दर से और नीचे आ गयी। इतनी गिरावट होने पर भी, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका की संरक्षणवादी प्रवृत्तियों और अमेरिका-ईरान के बीच भू-राजनैतिक तनावों के कारण अभी भी अनिश्चितताएं उच्च स्तर पर बनी हुई हैं। वैश्विक विनिर्माण, व्यापार और मांग के लिए कमजोर परिवेश के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर वर्ष 2019-20 की प्रथम छमाही में मंद होकर 4.8 प्रतिशत दर पर आ गई जोकि वर्ष 2018-19 की द्वितीय छमाही की 6.2 प्रतिशत से कम है। वास्तविक उपभोग की धीमी वृद्धि से प्रेरित वास्तविक निश्चित निवेश में तेजी से गिरावट से वर्ष 2018-19 की द्वितीय छमाही से वर्ष 2019-20 की प्रथम छमाही के दौरान जीडीपी वृद्धि में गिरावट की स्थिति उत्पन्न हुई है। हालांकि, सरकारी अंतिम उपभोग में पर्याप्त वृद्धि के सहारे, वर्ष 2019-20 की द्वितीय तिमाही में वास्तविक उपभोग वृद्धि की भरपाई हुई है। साथ-ही-साथ भारत के वैदेशिक क्षेत्र में वर्ष 2019-20 की प्रथम छमाही में और स्थिरता आई है, जहां चालू खाता घाटा (सीएडी) वर्ष 2018-19 में जीडीपी के 2.1 प्रतिशत से कम होकर वर्ष 2019-20 की प्रथम छमाही में 1.5 प्रतिशत पर आ गया है, प्रभावी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) हुआ है, पोर्टफोलियो प्रवाहों की बहाली हुई है और विदेशी मुद्रा भंडारों में वृद्धि हुई है। क्रूड की कीमतों में राहत से वर्ष 2019-20 की प्रथम छमाही में आयातों में कमी आई है और निर्यातों में तेजी से वृद्धि हुई है जो मुख्यतः सीएडी में संकुचन के फलस्वरूप संभव हुआ है। आपूर्ति पक्ष के संदर्भ में कृषि वृद्धि दर के कमजोर रहने के बावजूद, यह वर्ष 2018-19 की द्वितीय छमाही की तुलना में वर्ष 2019-20 की प्रथम छमाही में थोड़ी सी ऊपर रही है। खाद्य महंगाई में अस्थायी वृद्धि के कारण शीर्ष मुद्रास्फीति वर्ष 2019-20 की प्रथम छमाही में 3.3 प्रतिशत के स्तर से बढ़कर दिसंबर, 2019 में 7.4 प्रतिशत हो गई, जिसके वर्ष के अंत तक नीचे आने की प्रत्याशा है। दिसंबर, 2019 में सीपीआई-मूल और डब्ल्यूपीआई मुद्रा स्फीति का बढ़ना मांग-दबावों के बढ़ने का संकेत है।

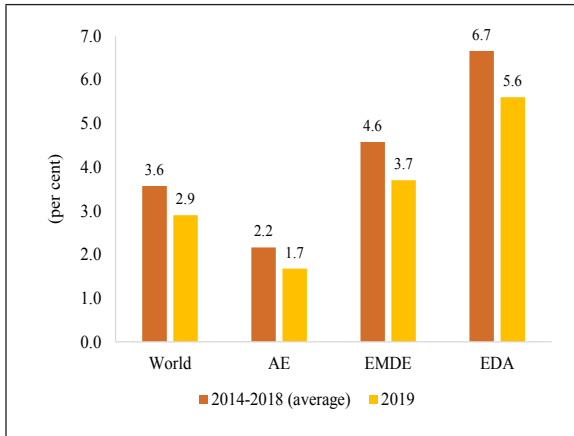
जीडीपी वृद्धि में मंदन गति को वास्तविक क्षेत्र पर अवरोध का कार्य करने वाले वित्तीय क्षेत्र से युक्त मंदवृद्धि चक्र की रूपरेखा के अंतर्गत समझा जा सकता है। मांग बढ़ाने के प्रयास के तहत, वर्ष 2019-20 में मौद्रिक नीति में काफी राहत दी गई है और आरबीआई द्वारा रेपो दर में 110 आधार बिंदुओं की कटौती की गई है। अर्थव्यवस्था में वित्तीय दबावों को स्वीकार करते हुए सरकार ने दिवाला एवं दिवालियापन संहिता (आईबीसी) के तहत दिवाला समाधान प्रक्रिया को गति प्रदान करने तथा विशेष रूप से संकटग्रस्त रीयल इस्टेट और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) क्षेत्रों के लिए साख व्यवस्था में राहत प्रदान करने की दिशा में इस वर्ष अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। निवेश बढ़ाने के लिए, विशेष रूप से राष्ट्रीय अवसंरचना रूपरेखा के तहत, अमल में लाए गए महत्वपूर्ण उपायों से वर्ष 2019-20 की द्वितीय छमाही और 2020-21 में विकास के लिए हरित शाखाएं पल्लवित होने की आशा है। वर्ष 2019-20 के लिए 5 प्रतिशत पर दर्ज भारत की जीडीपी वृद्धि के प्रथम अग्रिम प्राक्कलन के आधार पर यह आशा की जा सकती है कि वर्ष 2019-20 की द्वितीय छमाही में जीडीपी की वृद्धि दर ऊपर जाएगी। सरकार को तत्परता के साथ सुधारों को अमल में लाने के लिए अपने मजबूत जनादेश का उपयोग करना चाहिए ताकि वर्ष 2020-21 में अर्थव्यवस्था मजबूती के साथ उभर सके।

## वर्ष 2019-20 में वैश्विक अर्थव्यवस्था

1.1 आईएमएफ द्वारा प्रकाशित जनवरी-2020 के वैश्विक आर्थिक परिदृश्य (डब्ल्यूईओ) में वर्ष 2019 वैश्विक उत्पादन में वृद्धि दर का, वर्ष-2018 के 3.6 प्रतिशत और वर्ष-2017 के 3.8 प्रतिशत से गिरकर 2.9 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है। वर्ष-2019 में वैश्विक उत्पादन में वृद्धि दर, वर्ष-2009 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद सबसे धीमी रहने का अनुमान है जोकि विनिर्माण संबंधी गतिविधियों और व्यापारिक कार्यकलापों में भौगोलिक रूप से आई व्यापक गिरावट से उत्पन्न हुई है। अमेरिका तथा चीन के बीच स्थिर

प्रायः लेकिन अनिश्चित/व्यापारिक तनाव भी वैश्विक उत्पादन और व्यापार में आई गिरावट के लिए जिम्मेदार हैं। इसी प्रकार, उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की वृद्धि दर, जो वर्ष 2017 में 2.5 प्रतिशत थी, वर्ष-2018 में घटकर 2.2 प्रतिशत हो गई और वर्ष-2019 में इसके और कम होकर 1.7 प्रतिशत तक जाने का अनुमान है (चित्र: 1)। ओईसीडी (आर्थिक सहयोग और विकास संगठन) देशों के समूह ने भी अपनी वृद्धि दर में वर्ष 2017 के 2.6 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2018 में 2.3 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की है, वर्ष 2019 में इसके 1.7 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है। डब्ल्यूईओ ने वर्ष 2020 में वैश्विक उत्पादन की घटती वृद्धि दर

चित्र 1: वैश्विक उत्पादन/में वृद्धि



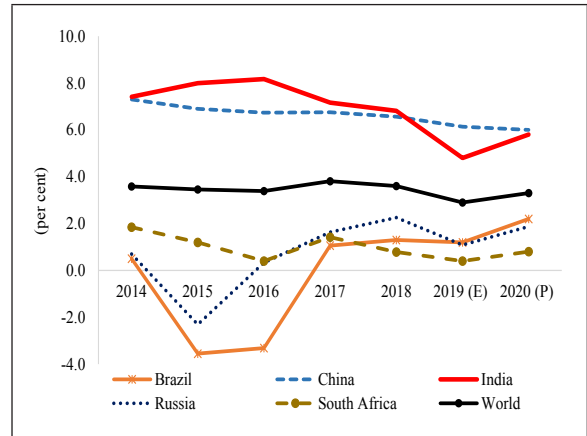
आंकड़ा स्रोत: वैश्विक आर्थिक परिदृश्य, अक्टूबर 2019 डाटाबेस तथा जनवरी 2020 अपडेट

नोट/टिप्पणी: ए ई: उन्नत अर्थव्यवस्थाएं, ईएमडीई: उभरते बाजार और विकासोन्मुख अर्थव्यवस्थाएं, ईडीएमई: उदीच्यमान तथा विकासशील एशिया

को मामूली वृद्धि के साथ 3.3 प्रतिशत हो जाने का पूर्वानुमान लगाया है।

1.2 अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की तरह, भारत की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि दर भी वैश्विक उत्पादन के विकास के साथ संबंधित है, जैसा कि वर्ष 2015-16 की आर्थिक समीक्षा में विचार किया गया था। आश्चर्य की बात नहीं है कि 2017 के बाद से भारत की जीडीपी वृद्धि में आई गिरावट भी वैश्विक उत्पादन में आई गिरावट का ही परिणाम है। (चित्र-2) हालांकि वर्ष 2017 से पूर्व तीन वर्षों जब तक वैश्विक उत्पादन में गिरावट नहीं आई थी, जब भारत, समस्त विश्व से आगे बढ़ गया तथा 2014-18 में भारत की औसत संवृद्धि,

चित्र 2: ब्रिक्स के अलग-अलग देशों की संवृद्धि



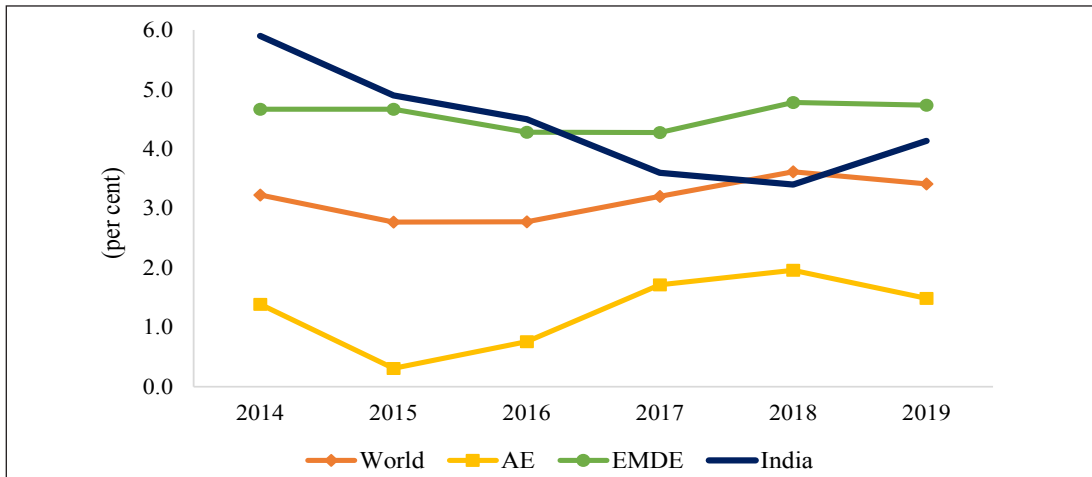
आंकड़ा स्रोत: वैश्विक आर्थिक परिदृश्य, अक्टूबर 2019 डाटाबेस तथा जनवरी 2020 अपडेट

नोट/टिप्पणी: ई: आईएमएफ (अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष) के प्राकलन, पी आईएमएफ (अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष) के अनुमान

उन्नत और उभरते बाजार, दोनों तरह की अर्थव्यवस्था के बीच किसी भी तुलनात्मक देश से काफी अधिक दर्ज की गई थी। जनवरी-2020 के डब्ल्यूईओ अपडेट में भारतीय अर्थव्यवस्था की संवृद्धि दर में वर्ष 2020 में 5.8 प्रतिशत तक वृद्धि का अनुमान लगाया गया है जिससे वैश्विक उत्पादन में सम्भाव्य तेजी में भारत के महत्वपूर्ण योगदान देने की उम्मीद है। वर्ष 2018-19 में नाममात्र कीमतों (नॉमिनल प्राइस) में भारत की जीडीपी 190.1 लाख करोड़ रुपये (2.7 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर) थी।

1.3 वर्ष -2019 में वैश्विक आर्थिक गतिविधियों के कमजोर होने के साथ-साथ, दुनिया भर में मुद्रास्फीति भी मन्दित रही (चित्र 3)। उन्नत और नई अर्थव्यवस्थाओं में

चित्र 3: देश के विभिन्न समूहों में उपभोक्ता कीमत वृद्धि



आंकड़ा स्रोत: वैश्विक आर्थिक परिदृश्य, अक्टूबर 2019 डाटाबेस तथा, राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यक्रम नोट/टिप्पणी: ए ई: उन्नत अर्थव्यवस्थाएं, ईएमडीई: उभरते बाजार और विकासोन्मुख अर्थव्यवस्थाएं, ईडीएमई: उदीप्यमान तथा विकासशील एशिया

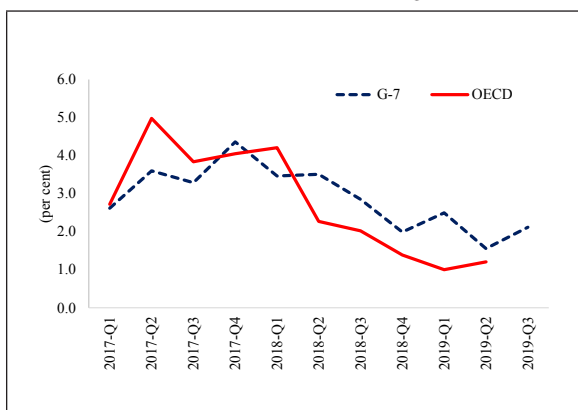
2. भारत के लिए वर्ष अप्रैल-मार्च और 2019 के लिए डाटा अप्रैल से दिसंबर है

उपभोक्ता मांग में गिरावट को दर्शाते हुए मुद्रास्फीति नरम हो गई। आपूर्ति पक्ष के संदर्भ में वर्ष 2019 में ऊर्जा की कीमतों में कमी होने से भी मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में मदद मिली। अप्रैल-दिसंबर 2019 में भारत की मुद्रास्फीति थोड़ा बढ़कर 4.1 प्रतिशत हो गई, जो 2014 में 5.9 प्रतिशत की तेज गिरावट के बाद 2018 में 3.4 प्रतिशत हो गई।

1.4 उपभोक्ता मांग में वैश्विक गिरावट ने औद्योगिक क्रियाकलाप को प्रभावित किया, जिसके फलस्वरूप वर्ष

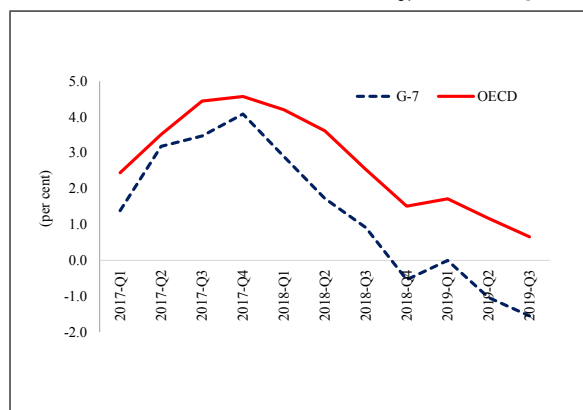
2019 में विश्व की अधिकांश प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में गिरावट आयी (चित्र 4 एवं 5)। विशेष रूप से, ऑटोमोबाइल उद्योग के वैश्विक उत्पादन में तेजी से गिरावट आयी, जिसका प्रमुख कारण मांग में कमी आना है। मांग में कमी आने का एक कारण यह है कि बहुत से देशों में प्रौद्योगिकी और उत्सर्जन मानकों में कई तरह के बदलाव हुए हैं। भारत के ऑटो उद्योग में भी इसी तरह की गिरावट आयी है (आईएमएफ के विश्व आर्थिक आउटलुक अक्टूबर, 2019 और जनवरी 2020)

चित्र 4: अचल निवेश की वृद्धि दर



डाटा स्रोत: ओ ई सी डी डाटाबेस  
टिप्पणी: कैलेंडर वर्ष के आधार पर तिमाही जी-7 का अर्थ विश्व में सात बड़ी उन्नत अर्थव्यवस्थाओं अर्थात कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के समूह से है।

चित्र 5: विनिर्माण उत्पादन के सूचक की वृद्धि



डाटा स्रोत: ओ ई सी डी डाटाबेस  
टिप्पणी: कैलेंडर वर्ष के आधार पर तिमाही ओ ई सी डी का अर्थ आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन से है जिसमें 36 सदस्य देश हैं।

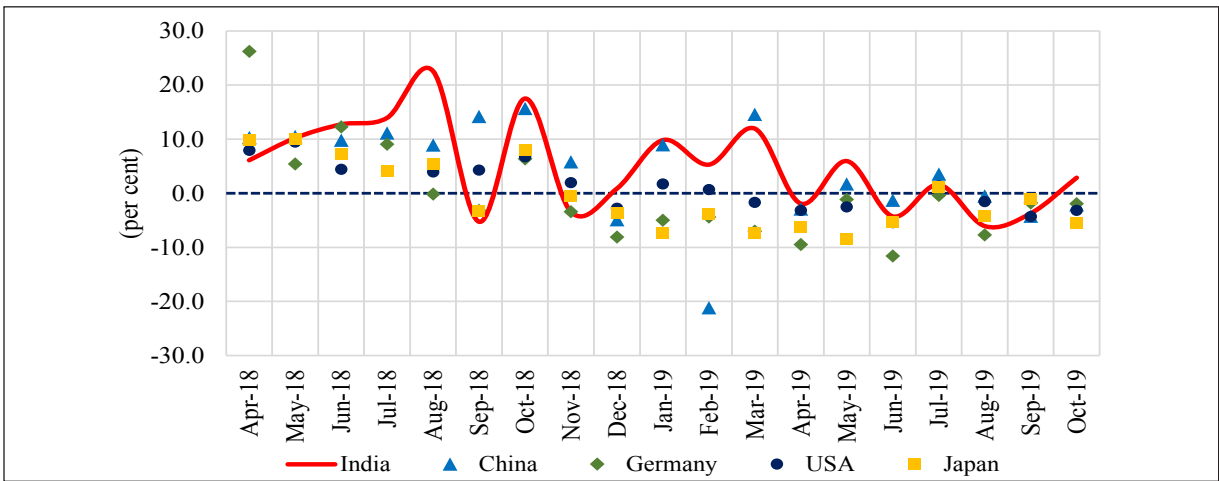
1.5 जैसे-जैसे वैश्विक औद्योगिक गतिविधि धीमी हुई, विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं से विनिर्माण निर्यात की वृद्धि दर में कमी आयी है। बढ़ते व्यापार तनावों के साथ-साथ व्यापार अनिश्चिताओं के बढ़ने से व्यापार संबंधी अनिश्चिताओं ने भी व्यवसाय के भरोसे में कमी आयी है जिसके फलस्वरूप व्यापारिक गतिविधियों में कमी आयी है। भारत का विनिर्माण निर्यात भी गिर गया है। (चित्र 6)।

### वर्ष 2019-20 में भारतीय अर्थव्यवस्था

#### अर्थव्यवस्था का आकार:

1.6 अक्टूबर 2019 के डब्ल्यूईओ ने वर्तमान अमेरिकी डॉलर मूल्यों पर जीडीपी का उपयोग करते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था के दुनिया में पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने का अनुमान लगाया है। उपर्युक्त उपलब्धि को हासिल करते ही भारत यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को पीछे छोड़ देगा। वर्ष 2019 में भारतीय

चित्र 6: गैर-कृषि, गैर-ईंधन व्यापारिक वस्तु निर्यात वृद्धि<sup>1</sup> दर



डाटा स्रोत: ट्रेड मैप डाटाबेस

तालिका 1: वर्तमान अमेरिकी डॉलर ट्रिलियन में जीडीपी के संदर्भ में दुनिया की शीर्ष 10 अर्थव्यवस्थाएं

क्र. सं.	देश	2017	2018	2019 (E)	2019 में स्थान में परिवर्तन
1	संयुक्त राज्य अमेरिका	19.5	20.6	21.4	-
2	चीन	12.1	13.4	14.1	-
3	जापान	4.9	5.0	5.2	-
4	जर्मनी	3.7	4.0	3.9	-
5	भारत	2.7	2.7	2.9	▲
6	यूनाइटेड किंगडम	2.6	2.8	2.7	▼
7	फ्रांस	2.6	2.8	2.7	▼
8	इटली	2.0	2.1	2.0	-
9	ब्राजील	2.1	1.9	1.8	-
10	कोरिया	1.6	1.7	1.6	-

डाटा स्रोत: विश्व आर्थिक आउटलुक, अक्टूबर 2019 डाटाबेस

टिप्पणी: ई: आई एम एफ के आकलन: ▲ का रैंक में सुधार; ▼ गिरावट का अर्थ रैंक का यथावत रहना

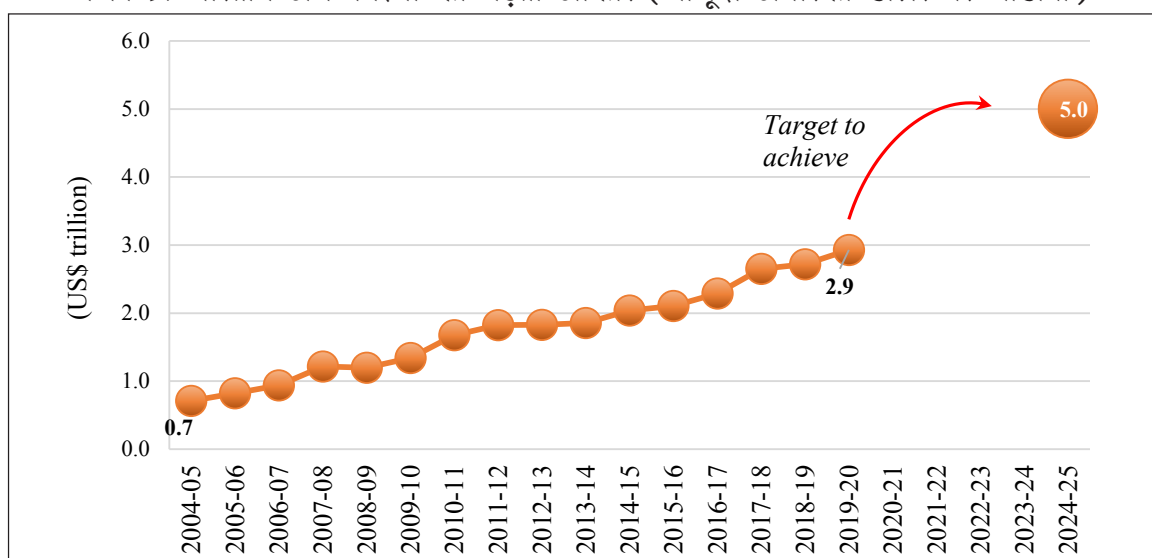
1. एचएस कोड 28 से 96 के तहत उत्पाद श्रेणियों से संबंधित कुल व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात को विनिर्माण निर्यात माना जाता है।

अर्थव्यवस्था का आकार अमेरिकी डॉलर 2.9 ट्रिलियन होने का आकलन किया गया है। (तालिका 1)

1.7 जुलाई, 2019 में, केंद्रीय बजट 2019-20 में माननीय प्रधानमंत्री के 2024-25 तक भारतीय अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाए जाने संबंधित दृष्टिकोण पर स्पष्ट बल दिया गया है। हालांकि, वैश्विक निर्गम में हास के कारण, इस वर्ष के लिए भारत के सकल घरेलू

उत्पाद में अपेक्षित वृद्धि की अपेक्षा कम वृद्धि होना इस उपलब्धि के लिए चुनौती बना हुआ है। इसके बावजूद भी, विगत पांच वर्षों (वार्षिक औसत वृद्धि की दर 7.5 प्रतिशत और मुद्रास्फीति की वार्षिक औसत दर 4.5), से स्थिर समष्टि अर्थशास्त्रीय घटनाचक्र के चलते वृद्धि के दिए गए भारतीय रिकॉर्ड से अपेक्षा की जाती है कि 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है (चित्र 7)।

चित्र 7: भारतीय अर्थव्यवस्था का बढ़ता आकार (मौजूदा अमेरिकी डॉलर पर जीडीपी)



स्रोत: राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और अंतर-राष्ट्रीय मुद्रा कोष

### जीवीए और जीडीपी वृद्धि

1.8 राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (एनएसओ) ने 2019-20 की प्रथम छमाही (एच 1) (अप्रैल-सितम्बर) में भारतीय जीडीपी में 4.8 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान लगाया है, जो 2018-19 की दूसरी छमाही (एच 2) (अक्टूबर-मार्च) में दर्ज की गई 6.2 प्रतिशत की अपेक्षा वृद्धि की कम है। इसके विपरीत आपूर्ति पक्ष

के संबंध में, “कृषि और आनुषंगिक क्रियाकलापों, और लोक प्रशासन, सुरक्षा, और अन्य सेवाओं, 2019-20 की प्रथम छमाही की वृद्धि दर 2018-19 की दूसरी छमाही की वृद्धि दर से उच्च थी, को छोड़कर सभी सैक्टरों द्वारा सामान्य तौर पर सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि के विवरण के अनुसार जीडीपी वृद्धि में योगदान किया है (तालिका 2)।

तालिका 2: वास्तविक सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) और जीडीपी (प्रतिशत) की तिमाहीवार वृद्धि

	2018-19				2019-20	
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2
मूल मूल्यों पर जीवीए	7.7	6.9	6.3	5.7	4.9	4.3
कृषि, वन एवं मत्स्य	5.1	4.9	2.8	-0.1	2.0	2.1
उद्योग	9.8	6.7	7.0	4.2	2.7	0.5
सेवाएं	7.1	7.3	7.2	8.4	6.9	6.8
बाजार मूल्यों पर जीडीपी	8.0	7.0	6.6	5.8	5.0	4.5

डाटा स्रोत: राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय।

1.9 मांग पक्ष के संबंध में, 2018-19 के मूल उपयोग की सुस्त वृद्धि से तुलना करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि 2019-20 के प्रथम छमाही में अचल निवेश की वृद्धि में गिरावट के कारण सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में गिरावट दर्ज की गई। हालांकि, विशेष रूप से सरकारी अंतिम उपयोग में महत्वपूर्ण उछाल से 2019-20 के दूसरे तिमाही में वास्तविक उपयोग

में वृद्धि प्रारंभ हो गई। 2019-20 की दूसरे तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद में निवल निर्यात का योगदान कम नकारात्मक हो गया, क्योंकि वास्तविक रूप से निर्यात का संकुचन आयात के संकुचन की तुलना में बहुत कम था। जीडीपी की कम वृद्धि और कच्चे तेल की घटती कीमत के कारण आयात में एक बड़ा संकुचन हुआ (तालिका 3)।

तालिका 3: जीडीपी की वास्तविक वृद्धि (प्रतिशत)

	2017-18	2018-19 (PE)	2019-20	
			Q1	Q2
सकल घरेलू उत्पाद	7.2	6.8	5.0	4.5
कुल उपयोग	8.6	8.3	4.1	6.9
सरकारी उपयोग	15.0	9.2	8.8	15.6
निजी उपयोग	7.4	8.1	3.1	5.1
अचल निवेश	9.3	10.0	4.0	1.0
माल और सेवाओं का निर्यात	4.7	12.5	5.7	-0.4
माल और सेवाओं का आयात	17.6	15.4	4.2	-6.9

स्रोत: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय

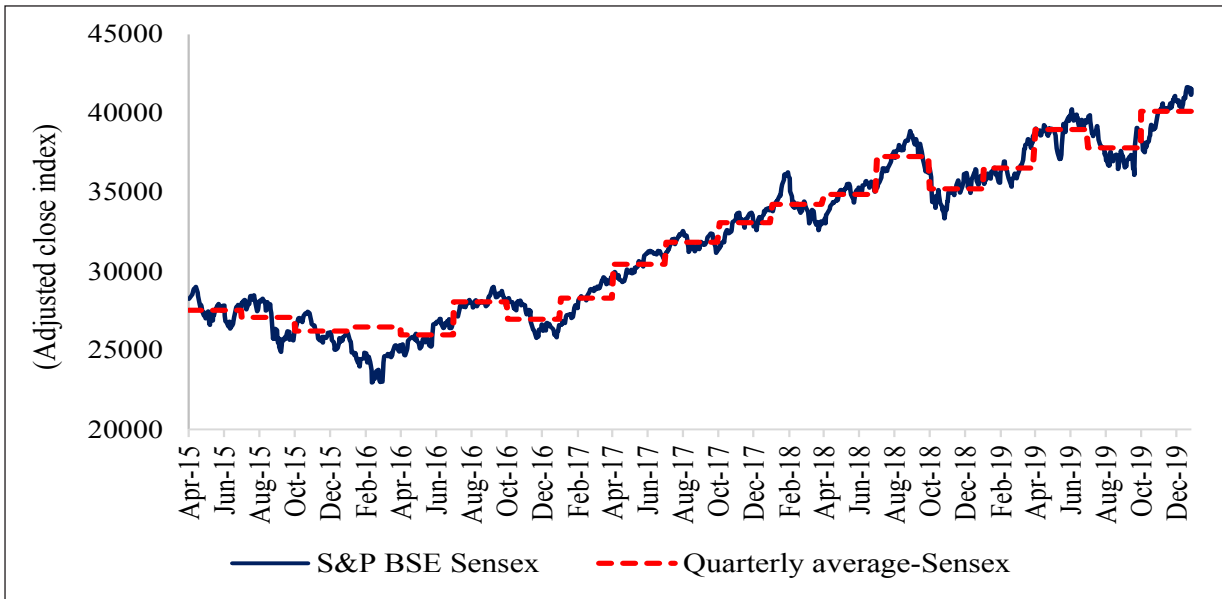
नोट: पीई-अंतिम अनुमान

1.10 लगातार छठी तिमाही में जीडीपी वृद्धि में गिरावट के बावजूद, शेयर बाजार देश के विकास की संभावनाओं को लेकर उत्साहित है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) का सेंसेक्स मार्च, 2019 की तुलना में दिसंबर, 2019 के अंत में 7.0 प्रतिशत अधिक हो गया (चित्र 8)। यह दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की वृद्धि में गिरावट और संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मौद्रिक नीति को आसान बनाए जाने की पृष्ठभूमि में निवेश के लिए भारत के एक आकर्षक गंतव्य बनने की बढ़ती धारणा को भी दर्शाता है। 2019-20 के पहले आठ महीनों में निवल एफडीआई और निवल विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) क्रमशः 24.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 12.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो कि 2018-19 के अवधि में प्राप्त अंतर्वाह से अधिक था।

1.11 भारत ने 2011-12 से 2012-13 की चौथी तिमाही में अपनी सबसे कम तिमाही जीडीपी वृद्धि दर्ज

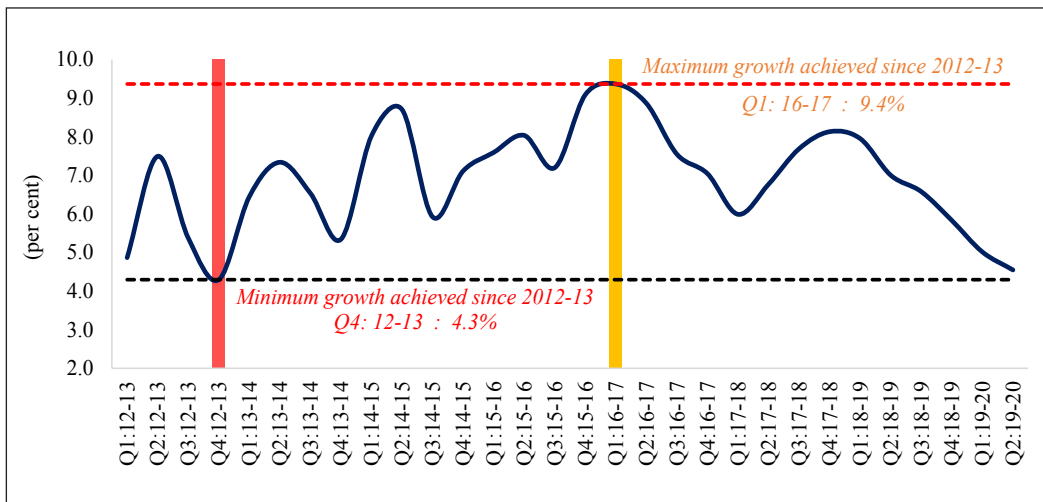
की है (चित्र 9)। 13 तिमाहियों के बाद, अर्थव्यवस्था ने 2016-17 की पहली तिमाही में 9.4 प्रतिशत की अपनी उच्चतम तिमाही वृद्धि प्राप्त की। पुनः इसके 13 तिमाहियों के बाद, अर्थव्यवस्था ने 2019-20 की दूसरी तिमाही में 4.5 प्रतिशत के साथ गिरावट दर्ज की। ऐसा प्रतीत होता है कि व्यापार चक्र की लंबाई लगभग 13 तिमाही है। 2018 में, 1996 से विकास के आंकड़ों को लेकर भारत में व्यापार चक्र माप पर किए गए एक अध्ययन (पांडे और अन्य (2018)) में ऐसे ही परिणाम दर्शाए गए हैं। उनका अध्ययन इस बात को दर्शाता है कि जब जीडीपी में वृद्धि हो रही हो तब से व्यापार चक्र का औसत 12 तिमाही का होता है। हालांकि, मंदी के दौर में, व्यापार चक्र औसतन घटकर 9 तिमाही तक का हो जाता है। तदनुसार, 2019-20 की दूसरी छमाही में वृद्धि में पुनरुत्थान होने का अनुमान किया जा रहा है।

चित्र 8: बीएसई सेंसेक्स में परिवर्तन



आंकड़ों का स्रोत: बीएसई

चित्र 9: वास्तविक जीडीपी में तिमाही वार वृद्धि



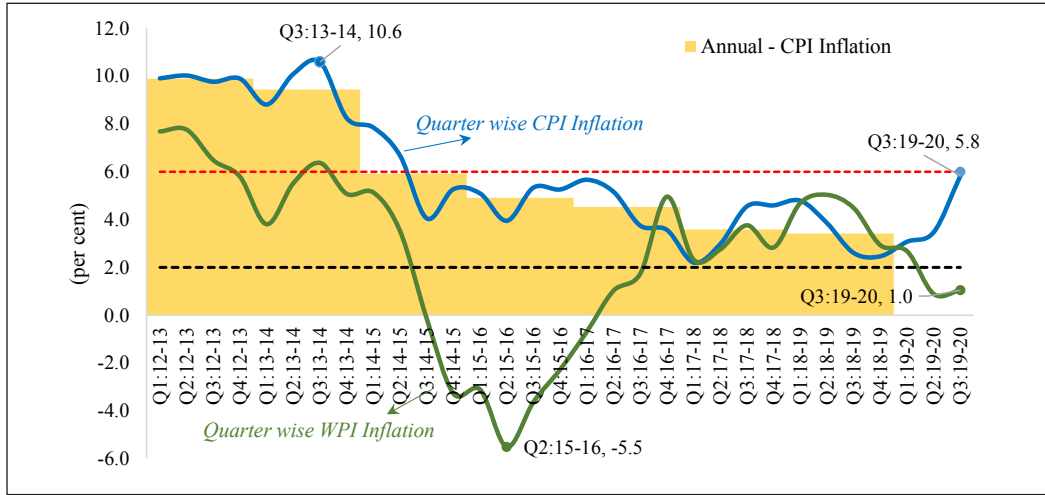
आंकड़े का स्रोत: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय

### मुद्रास्फीति

1.12 2019-20 की पहली छमाही में, सी.पी.आई. (हेडलाइन) 3.3 प्रतिशत मुद्रास्फीति प्रतिशत का आंकलन किया गया था जो कि पिछले वर्ष की दूसरी छमाही की सी.पी.आई. (हेडलाइन) मुद्रास्फीति से थोड़ा अधिक है। दिसंबर, 2019 माह में हेडलाइन मुद्रास्फीति में 7.35 प्रतिशत तक का इजाफा रहा है, जिसमें मुख्यतः आपूर्ति पक्ष के घटकों का योगदान था। देश के कई

हिस्सों में बेमौसम वर्षा और बाढ़ जैसी स्थिति के कारण खाद्य की कीमतों में स्पष्ट रूप से वृद्धि हुई, जिससे कृषि संबंधी फसल का उत्पादन प्रभावित हुआ था। दूसरी तरफ, थोक कीमत सूचकांक (डब्ल्यू.पी.आई) मुद्रास्फीति में अप्रैल, 2019 में 3.2 प्रतिशत से दिसम्बर, 2019 में 2.6 प्रतिशत तक की तेजी से गिरावट आई, जो अर्थव्यवस्था में मांग संबंधी दबाव की दुर्बलता (कमजोरी) को प्रतिबिम्बित करती है। (चित्र 10)

चित्र 10: सी.पी.आई. और डब्ल्यू.पी.आई. मुद्रास्फीति



आंकड़ों का स्रोत: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय और उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डी.पी.आई.आई.टी.)

1.13 कोर मुद्रास्फीति (हेडलाइन मुद्रास्फीति घटा खाद्य व ईंधन मुद्रास्फीति) अर्थव्यवस्था में मांग की स्थिति को प्रतिबिम्बित करती है। सी.पी.आई. कोर मुद्रा स्फीति में 2018-19 की पहली तिमाही में 6.3 प्रतिशत से 2019-20 की दूसरी तिमाही में 4.3 प्रतिशत तक शिथिलन रहा है, जिससे अर्थव्यवस्था में मांग संबंधी दाबव की कमजोरी भी प्रतिबिम्बित होती है। जी.डी.पी. अपस्फीतिकारक द्वारा प्रग्रहित, कोर सी.पी.आई. और डब्ल्यू.पी.आई. मुद्रास्फीति ने एक साथ मुद्रास्फीति को संतुलित किया, जिसमें 2018-19 की दूसरी छमाही में 3.7 प्रतिशत से 2019-20 की पहली छमाही में 2.1 प्रतिशत तक की गिरावट हुई। इससे जी.डी.पी. की मौद्रिक वृद्धि में भी काफी कमी आई।

#### रोजगार: औपचारिक बनाम अनौपचारिक

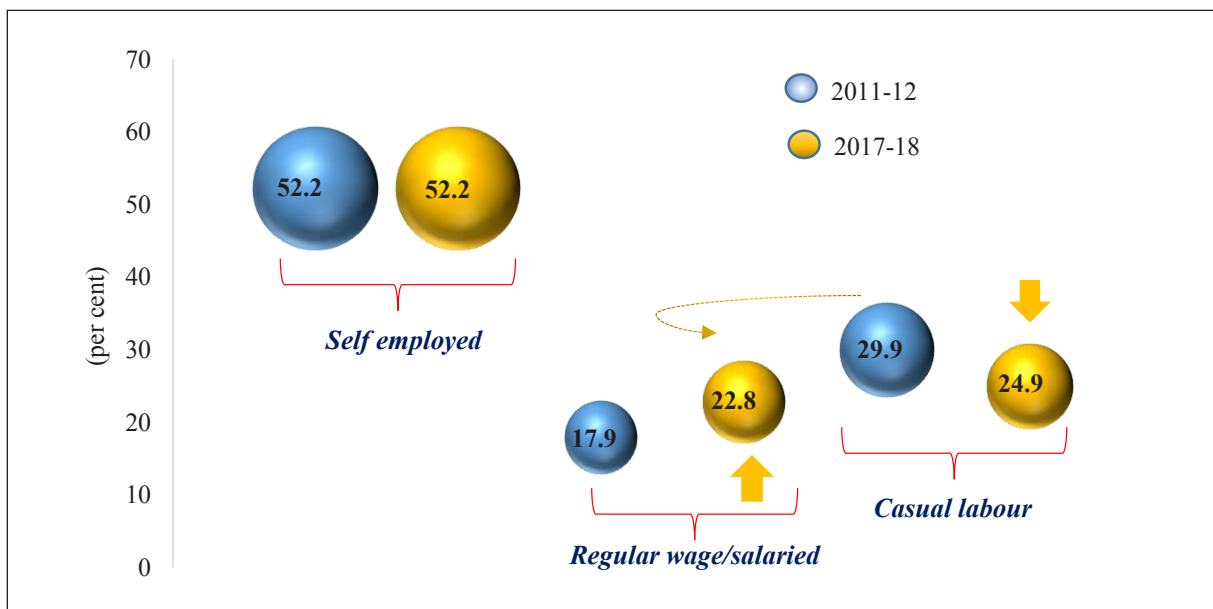
1.14 चूंकि अर्थव्यवस्था के औपचारिकीकरण में बढ़ोत्तरी के लिए कई नीतियां लागू की गई हैं, अतः इसके प्रभाव की जांच करना महत्वपूर्ण हो गया है। कार्यप्रणाली और नमूना चयन संबंधी डिजाइन में परिवर्तन के कारण, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पी.एल.एफ.एस.) पर आधारित श्रम बाजार प्राक्कलन राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एन.एस.एस.ओ.) द्वारा संचालित रोजगारी-बेरोजगारी पर प्रारंभिक पंचवर्षिक सर्वेक्षण के परिणामों से तुलनीय नहीं है। फिर भी औपचारिक क्षेत्र की नौकरियों (जॉब्स) में बर्धित नियोजनीयता में

परिवर्तन पर रोशनी डालने के लिए सीमित तुलनीयता लाने का प्रयास किया गया है।

1.15 रोजगार पर नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 'नियमित वेतन' द्वारा तथा अधिकृत औपचारिक रोजगार की हिस्सेदारी में 2011-12 में 17.9 प्रतिशत से 2017-18 से 22.8 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है (चित्र: 11)। नियमित वेतन/वैतनिक समूह की हिस्सेदारी में यह 5 प्रतिशत अंक की वृद्धि आकस्मिक कामगारों की हिस्सेदारी में 5 प्रतिशत अंक की कमी के कारण हुई है, जो अर्थव्यवस्था में औपचारिकीकरण को प्रतिबिम्बित करती है। परिणाम स्वरूप, पूर्ण शब्दों में, ग्रामीण क्षेत्रों में 1.21 करोड़ और शहरी क्षेत्रों में 1.39 करोड़ के साथ सामान्य स्थिति वर्ग में लगभग 2.62 करोड़ नई नौकरियों की महत्वपूर्ण उछाल आई थीं ध्यान से देखने पर, नियमित वेतन/वैतनिक कर्मचारी वर्ग में महिला कामगारों के अनुपात में इस वर्ग में महिला कामगारों के लिए 0.7 करोड़ नई नौकरियों के साथ 8 प्रतिशत अंकों तक की (2011-12 में 13 प्रतिशत से 2017-18 में 21 प्रतिशत तक की) वृद्धि हुई है। आकस्मिक श्रम में गिरावट मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्र से हुई है, जहां ग्रामीण श्रमिक कृषि से औद्योगिक और सेवा संबंधी कार्यकलाप की ओर स्थांतरित हुए हैं। शहरी क्षेत्र में, ये स्व-रोजगार से वैतनिक नौकरियों में रोजगार का परिवर्तन हुआ है (चित्र 11)।



चित्र 11: रोजगार में स्थितियों के माध्यम से सभी उम्र के सामान्य स्थिति के श्रमिकों का वितरण (पीएस + एसएस)



डाटा स्रोत: आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, 2017-18 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

टिप्पणी: पीएस-मुख्य स्थिति, एस.एस.-सहायक स्थिति

1.16 वित्तीय वर्ष मार्च 2018 के अंत तक उद्योगों का अनंतिम वार्षिक सर्वेक्षण संगठित निर्माण क्षेत्र में रोजगार वृद्धि को दर्शाता है। 2014-15 और 2017-18 के मध्य में कुल श्रमिकों की संख्या में 14.7 लाख की बढ़ोत्तरी हुई है और संगठित निर्माण क्षेत्र में लगे हुए कुल श्रमिकों की बढ़ोत्तरी 17.3 लाख हो गई है।

### राजकोषीय स्थिति

1.17 2019-20 में केन्द्र का वित्तीय घाटा बजट में 7.04 लाख करोड़ रुपये था (सकल घरेलू उत्पाद का 3.3 प्रतिशत) जबकि 2018-19 में प्रति वर्ष 6.49 लाख करोड़ रुपये (सकल घरेलू उत्पाद का 3.4 प्रतिशत) था। (चित्र 12) 2019-20 के प्रथम आठ महीनों में वित्तीय घाटा बजट का 114.8 प्रतिशत था।

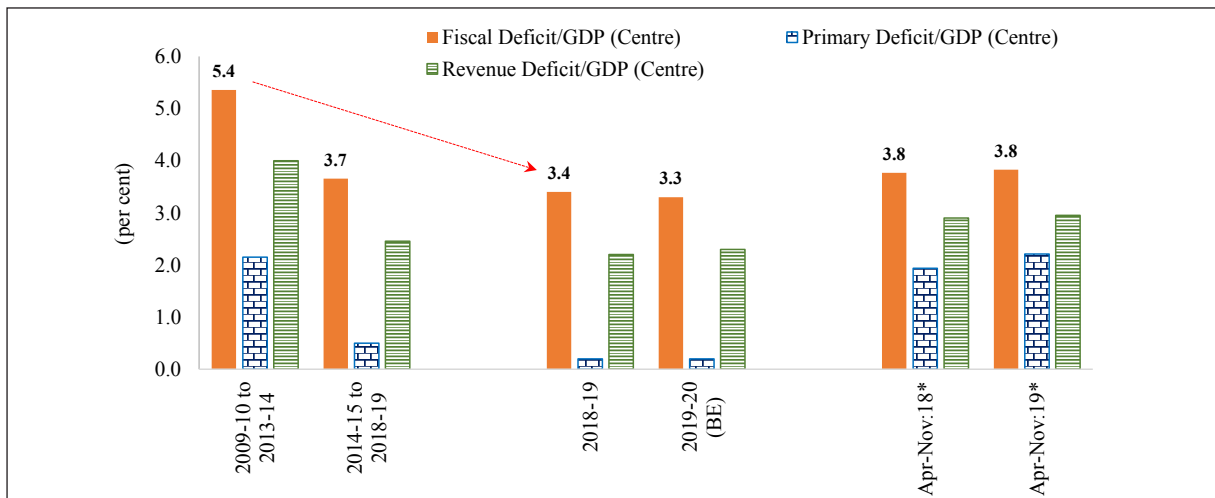
1.18 केन्द्र की निवल कर राजस्व, जो 2018-19 पीए के सापेक्ष 2019-20 बीई में 2.5 प्रतिशत से अधिक बढ़ने की परिकल्पना की गई थी, वह 2019 में अप्रैल से नवंबर के दौरान 2.6 प्रतिशत तक बढ़ गया था, तथापि समवर्ती पिछले वर्ष की अवधि में वृद्धि दर इसकी आधी थी) यह मुख्य रूप में 2019-20 के प्रथम आठ महीनों के दौरान सकल कर राजस्व (जीटीआर) में कम

वृद्धि (0.8) प्रतिशत का परिणाम था, जो 2018-19 (तालिका 6, अध्याय 2) की समवर्ती अवधि में वृद्धि 7.1 प्रतिशत थी। वर्ष 2019 के अप्रैल-नवंबर माह के दौरान अप्रत्यक्ष कर के सबसे बड़े घटक माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के संग्रह में 4.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। हालांकि केन्द्र का संचयी जीएसटी में वृद्धि अक्टूबर, 2019 में शुरू हुई थी और नवम्बर एवं दिसम्बर 2019 में भी जीएसटी संग्रह में वृद्धि बनी रही थी।

1.19 जीएसटी के (जुलाई, 2017) लागू होने से विशेषरूप में (केन्द्र + राज्य) 2019 के नवम्बर माह में जीएसटी संग्रह तीसरा सबसे बड़ी मासिक संग्रह था। 2019 के अप्रैल-दिसंबर में सकल जीएसटी राजस्व ने 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक का संग्रह पांच बार पार किया था और दिसम्बर, 2019 में राजस्व संग्रह 1.03 लाख करोड़ रुपये हो गया था। यह कर अनुपालन और राजस्व संग्रहों में सुधार के साथ-साथ एक पुनरूत्थान वाली अर्थव्यवस्था के प्रतिबन्ध के रूप में सरकार द्वारा किए गए ठोस प्रयासों का परिणाम हो सकता है।

1.20 व्यय की तरफ से, केन्द्रीय सरकार का बजटीय व्यय, पूर्ववर्ती वर्ष की इसी अवधि से बढ़ा, जो बजट

चित्र 12: जी.डी.पी. के प्रतिशत के रूप में सकल राजकोषीय घाटा (केन्द्र)



आंकड़ा स्रोत: संघीय बजट और सी जी ए

टिप्पणी \*: 2018 के आंकड़े 2018-19 के जीडीपी (पीई) आंकड़ों की तुलना में हैं तथा 2019 के आंकड़े अनंतिम हैं और 2019-20 की बजटी जीडीपी की तुलना में हैं।

का लगभग 12.8 प्रतिशत विस्तार हुआ और अप्रैल से नवंबर 2019 में बजट प्रावधान का 60 प्रतिशत अंश खर्च हो गया। 2019-20 में इसी अवधि के दौरान पूंजीगत व्यय 2018-19 की इसी अवधि की तुलना में लगभग तीन गुणा बढ़ा है। साथ ही 2019-20 के इन्हीं महिनों के दौरान राजस्व व्यय थी पूर्ववर्ती वर्ष की इसी अवधि की तुलना में उच्चतर दर से बढ़ा (अध्याय 2, चित्र 8)।

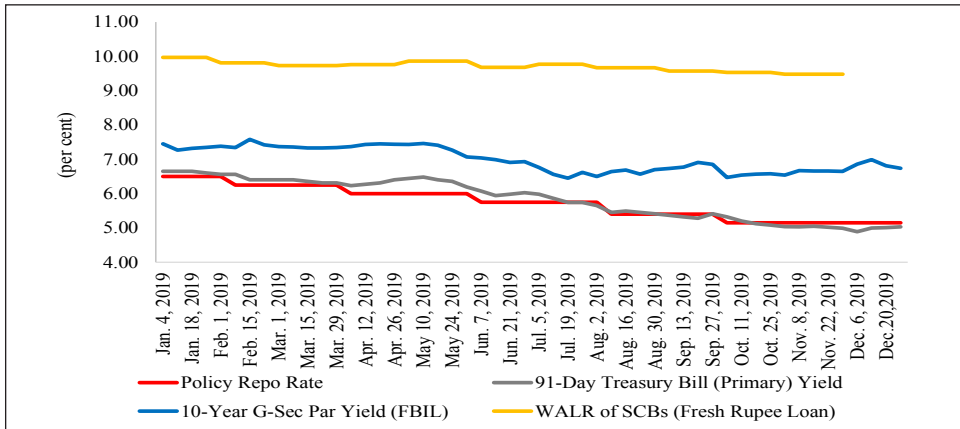
### मौद्रिक नीति

1.21 जून 2019 के बाद में बैंकों की नकदी की स्थिति सुखद रही है और तब से यह स्वस्थ बनी हुई है (अध्याय 4, चित्र 5)। औसत दैनिक निवल अवशोषण जून 2019 में रु. 45.6 हजार करोड़ से बढ़कर दिसंबर 2019 में रु. 256.4 हजार करोड़ हो गया। टिकाऊ नकदी अंतःक्षेपण, चार खुले बाजार में प्रतिभूतियों के क्रय - विक्रय (ओएमओ) के क्रय नीलामियों द्वारा और यू.एस. \$5 बिलियन के क्रय विक्रय के विनिमय नीलामी द्वारा किया गया। बैंकिंग प्रणाली में पर्याप्त नकदी भारत शीघ्रवाधि मुद्रा दर में भी परिलक्षित है, जो मुख्यतः चल निधि (नकदी) समायोजन सुविधा (एन च एफ) कॉरिडोर के भीतर व्यापारित होता है (एन च एफ

कॉरिडोर रेपो और रिवर्स रेपो दर के बीच कीमत लागत अंतर है) (अध्याय 4, चित्र 6)।

1.22 भारतीय रिज़र्व बैंक उदार बना रहा चूंकि इसने फरवरी 2019 से नीति रेपो दर में 135 आधार अंकों की कटौती की बैंकों में अतिशय नकदी सहित दर कटौती से ब्याज दरों में कमी के रूप में अंतरित होना संभावित है। यद्यपि, यह अंतरण विविध बाजार क्षेत्रों में प्रसारित हुआ (चित्र 13)। इस अवधि के दौरान अल्पावधि राजकोषीय बिलों को प्रेषण पूर्ण था जबकि दीर्घावधि प्रतिभूतियों के लिए यह आंशिक था। ऋण बाजार में प्रेषण भी आंशिक था, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (एससीबीज) द्वारा भारत औसत ऋण दर (डब्ल्यू ए एल आए) ताजा रूपे ऋण पर फरवरी से नवंबर 2019 के बीच केवल 33 आधार अंकों (बीपीएस) तक घटी है। अतः आरबीआई द्वारा दर कटौतियों में एक चौथाई से कम, बैंकों द्वारा नए ऋणदाताओं को अंतरित कर दी गई। फरवरी और नवंबर 2019 के बीच निधि आधार की उधार की दर (एमसीएलआर) की 1-वर्षीय सीमांत लागत की माध्यिका 49 बीपीएस तक कम की गई; जो आरबीआई द्वारा कटौती के लगभग एक तिहाई का अंतरण प्रदर्शित करता है।

चित्र 13: नीति दर, प्राप्ति तथा ऋण दर



आंकड़ों का स्रोत: आर बी आई।

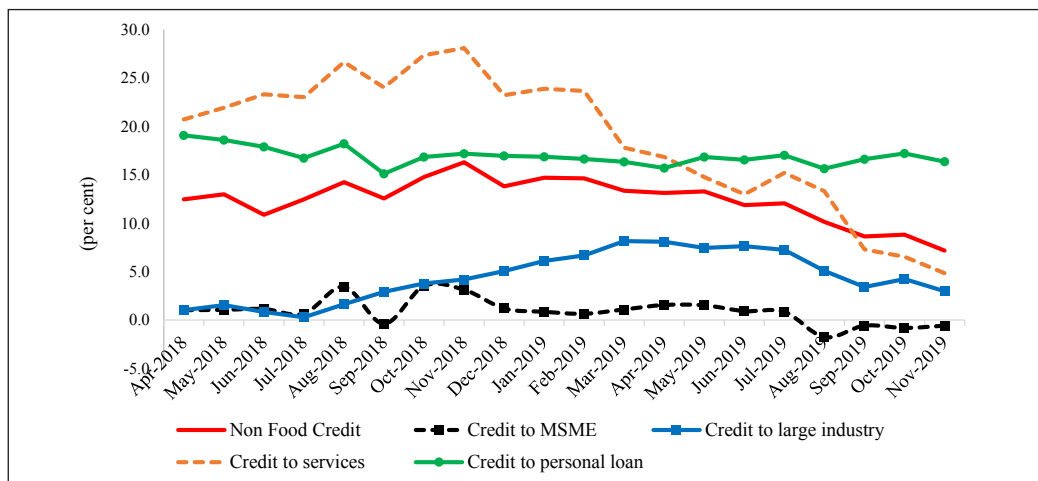
टिप्पणी: डब्ल्यू ए एलआर से तात्पर्य है भारत औसत ऋण दर।

**साख वृद्धि**

1.23 बैंक साख की वृद्धि, जो 2018-19 की प्रथम छमाही (एच 1) में उठ रही थी, 2018-19 की (दूसरी छमाही) (एच 2) में कम होने लगी और 2019-20 की (प्रथम छमाही) (एच 1) में और कम हो गई। यह कमी व्यक्तिगत ऋण को छोड़ खाद्येतर साख के सभी मुख्य खण्डों में मजबूत गति चलती रही। साख वृद्धि में सर्वाधिक कमी सेवा क्षेत्र में हुई। हाल ही के महीनों में उद्योगों की साख वृद्धि में काफी कमी दर्ज की गई, एमएसएम ई क्षेत्र तथा भारी उद्योगों दोनों में ही। कृषि तथा अनुषंगी गतिविधियां साख की उच्चतर वृद्धि से लाभन्वित हुई (चित्र 14)।

1.24 साख वृद्धि में कमी का मुख्य कारण बैंकों की जोखिम से बचने की बढ़ती हुई प्रवृत्ति है जिसने अनर्जक परिसंदाओं (एनपीए) के बढ़ने को सीमित किया है। साख वृद्धि में शिथिलता का कारण बैंकों द्वारा गैर-निष्पादक परिसंपदाओं के जमाव से बचने की जोखिम विरति को माना गया है। दिसंबर 2016 तथा जून 2019 के मध्य 2000 के अधिक कारपोरेट दिवालियापन संकल्प प्रक्रिया को दाखिल किए जाने के बावजूद ऐसी स्थिति है। आईबीसी प्रक्रिया ने गैर-निष्पादक परिसंपदाओं (एनपीए) को मार्च 2018 में 11.2 प्रतिशत से घटाकर मार्च 2019 में 9.3 प्रतिशत तक लाने में

चित्र 14: खाद्येतर बैंक साख की वृद्धि



आंकड़ों का स्रोत: आर बी आई

टिप्पणी: चयनित 41 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की क्षेत्रीय साख की वृद्धि।

अपनी भूमिका निभाई है। हालांकि, एनपीए अनुपात अगले छः माह अर्थात् सितंबर, 2019 में 9.3 प्रतिशत ही बना रहा।

1.25 सरकारी क्षेत्रों (जी-सेक) में सुगम निवेश की संभावना संभवतः अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) द्वारा दर्शाए जा रही जोखिम विरति के पूरक के रूप में कार्य कर रही है। वर्ष 2019-20 के प्रथम आठ महीनों के दौरान, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों ने पिछले वर्ष की संगत अवधि में जमा धानराशि के बारबर राशि को ही इनमें जमा किया। तथापि, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों ने सरकारी क्षेत्र में वर्तमान वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में अपने कर्ज उठाव को 4/5 भाग से अधिक घटाते हुए तीन गुना राशि के निवेश की योजना

बनाई है। ऐसा प्रतीत होता है कि निजी क्षेत्र को ऋण दिए जाने के प्रति जोखिम प्रतिकूलता में वर्ष 2019 में वृद्धि हुई है (तालिका 4)

1.26 निजी क्षेत्र को ऋण देने संबंधी जोखिम विरति सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के संबंध में अपेक्षाकृत अधिक प्रतीत होती है। जैसा कि चित्र 15 दर्शाता है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से ऋण की वृद्धि निजी क्षेत्र के बैंकों की साख वृद्धि भी दिसंबर 2018 के पश्चात् तेजी से कम हुई है।

#### बाह्य क्षेत्र निष्पादन

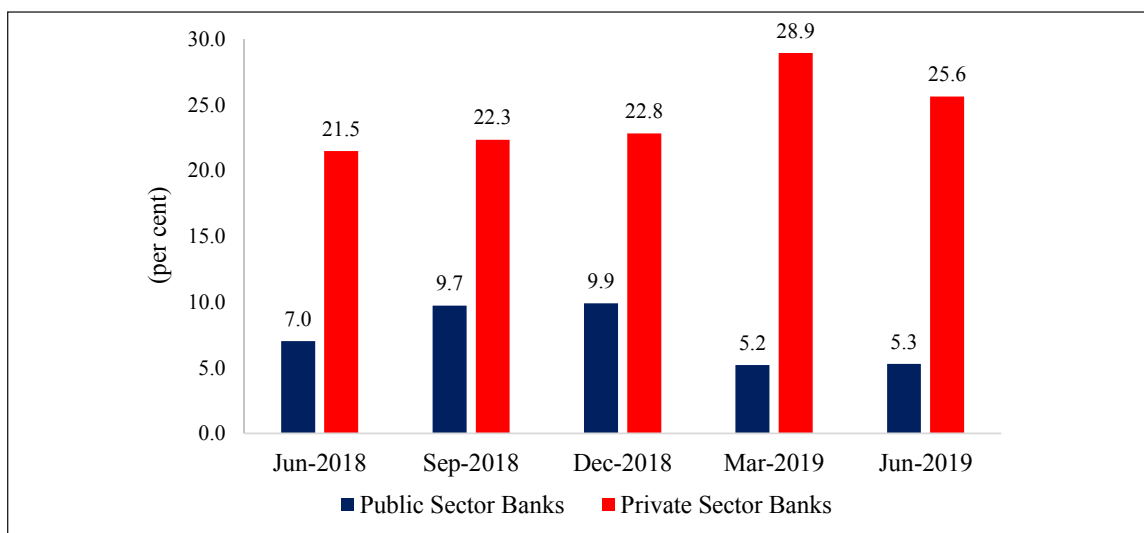
1.27 अक्टूबर एवं नवंबर, 2019 माह में पिछले वर्ष के तदनरूपी महीनों की प्रमुख वस्तु समूह के निर्यात की

तालिका 4: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक साख (लाख करोड़ रुपए में)

	अप्रैल-नवंबर	
	2018-19	2019-20
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की निवल साख	5.07	0.89
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की निवल समग्र जमा राशि	3.87	3.85
वृद्धिशील ऋण-जमा अनुपात (प्रतिशत)	131.0	23.1
सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	1.07	3.37

डाटा स्रोत: आरबीआई

चित्र 15: सार्वजनिक व निजी क्षेत्र के बैंकों की साख में वृद्धि।



डाटा स्रोत: आरबीआई

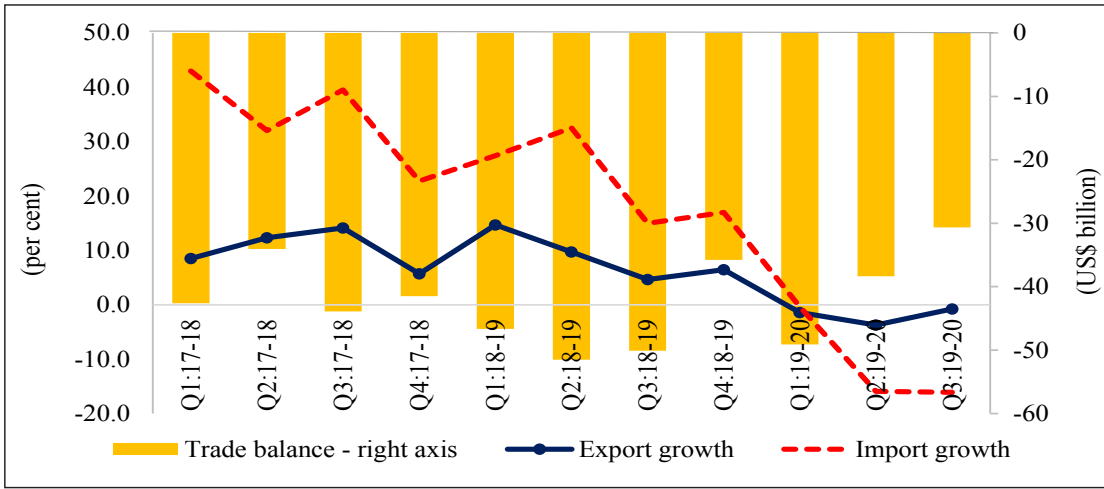
तुलना में सकारात्मक वृद्धि देखी गई है जबकि प्रमुख वस्तु समूह के आयात में कमी दर्ज की गई है। हालांकि आयात की तुलना में निर्यात व्यापार के धीमें संकुचन से वर्ष 2019-20 के व्यापार संतुलन में सुधार देखा गया है। (चित्र 16)

1.28 आयात बिल का संकुचन आंशिक तौर पर वर्ष 2018-19 की तुलना में चालू वर्ष में तेल की कीमतों में हुई गिरावट के कारण हुआ है, चित्र 17 जबकि निर्यात का धीमा संकुचन वैश्विक गतिविधि की प्रगति के फलस्वरूप हुआ है। चित्र 18 जुलाई, 2019 से वास्तविक

विनियम दर का अवमूल्यन भारत के निर्यात में पुनः सुधार के लिए सहायक हो सकता है, यद्यपि निर्यात में विनियम दर अवमूल्यन का योगदान स्पष्ट करने वाले साक्ष्य अस्पष्ट दिखाई देते हैं। (खंड-1, अध्याय-5)

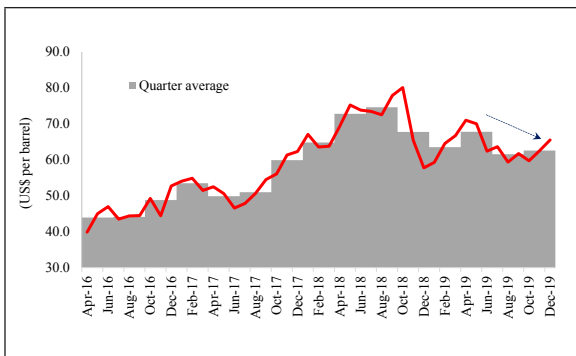
1.29 सेवा निर्यात के धीमी वृद्धि के बावजूद सेवा लेखा का व्यापार शेष वर्ष 2019-20 में सकारात्मक रहा है। सेवा लेखा में व्यापार अधिशेष वर्ष 2018-19 में एच-1 के 38.9 बिलियन यूएस डॉलर की तुलना में वर्ष 2019-20 में 40.5 बिलियन यूएस डॉलर रहा है। (चित्र 19)

चित्र 16: व्यापारिक निर्यात एवं आयात में वृद्धि



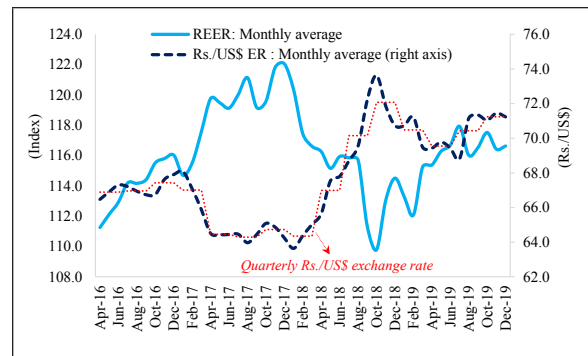
डाटा स्रोत: वाणिज्यिक विभाग, वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय

चित्र 17: कच्चा तेल कीमतें ( भारतीय बास्केट ) यूएस डालर प्रति बैरल



डाटा स्रोत: पेट्रोलियम आयोजना एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ

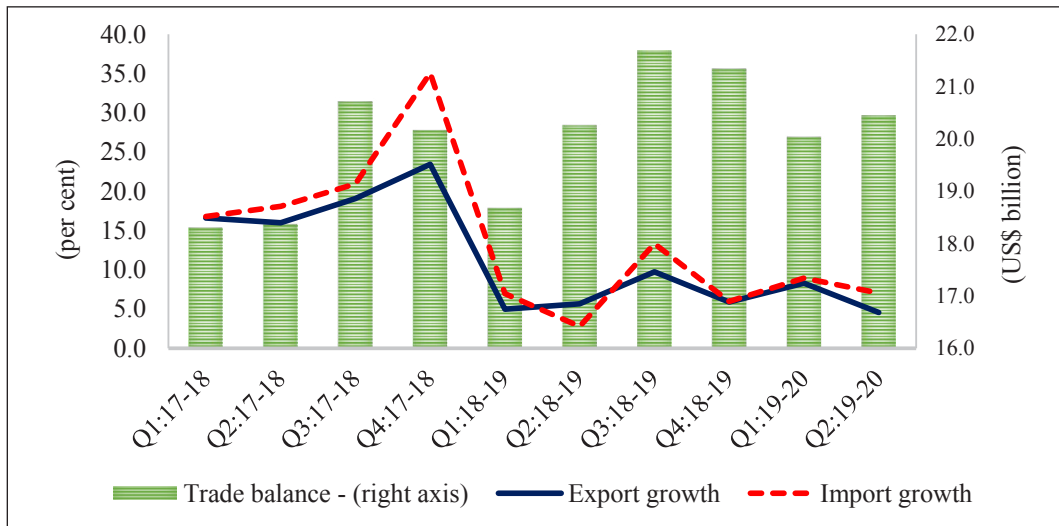
चित्र 18: भारतीय रुपए की विनियम दर



डाटा स्रोत: आरबीआई

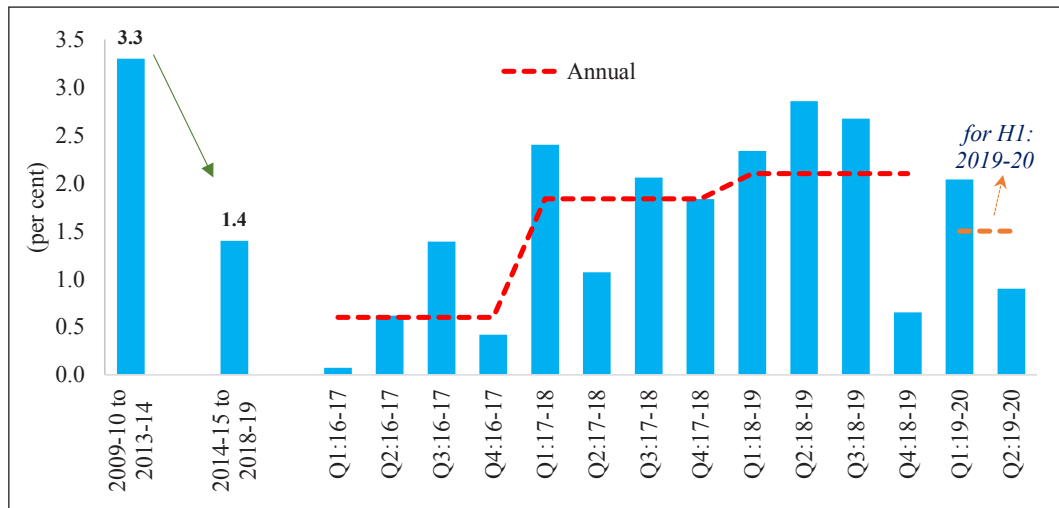
टिप्पणी: आरईईआर वास्तविक प्रभावी विनियम दर को दर्शाती है। (36 मुद्रा व्यापार भार)

चित्र 19: सेवा निर्यात एवं आयात में वृद्धि



डेटा स्रोत: आरबीआई

चित्र 20: जीडीपी के प्रतिशत के रूप में चालू लेखा घाटा



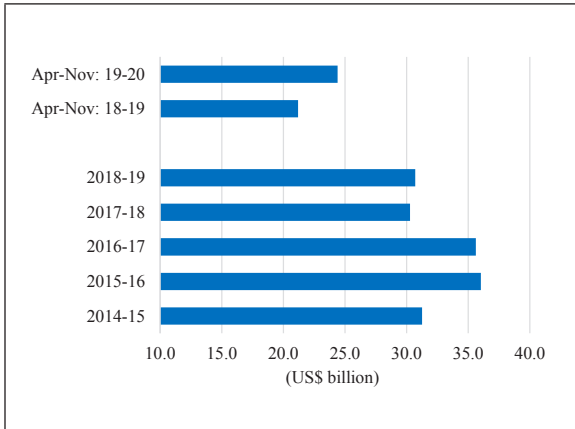
डेटा स्रोत: आरबीआई

1.30 निम्न चालू लेखा घाटा (सीएडी) देश की न्यूनीकृत बाह्य ऋणग्रस्तता को दर्शाता है जिससे घरेलू आर्थिक नीति की बाह्य प्रभावों पर निर्भरता घट जाती है। सीएडी, जो वर्ष 2018-19 के 2.1 प्रतिशत थी, में वर्ष 2019-20 के प्रथम छमाही (एच 1) में व्यापार घाटे में महत्वपूर्ण कटौती के चलते 1.5 प्रतिशत का सुधार हुआ है। (चित्र 20)

1.31 विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) बाह्य उधारों की तुलना में वित्तपोषण का अधिक स्थिर स्रोत

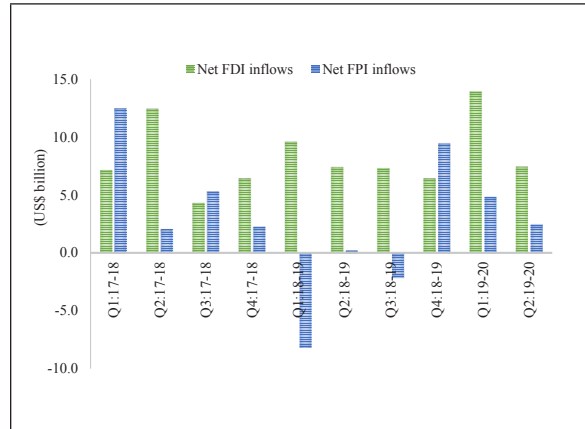
मुहैया कराता है। वर्ष 2014-19 के दौरान भारत में आईएफडीआई पिछले पांच वर्षों की तुलना में महत्वपूर्ण रही है; यह प्रवृत्ति वर्ष 2019-20 में यथावत् जारी रही (चित्र 21)। वर्ष 2019-20 के पहले 8 महीनों में देश में आई सकल एवं निवल एफडीआई वर्ष 2018-19 की तदनुसूची अवधि में प्राप्त प्रवाह से अधिक रही है। वर्ष 2019-20 के एच 1 में निवल एफपीआई प्रवाह भी वर्ष 2018-19 के एच-1 के 7.3 बिलियन यूएस डॉलर के बहिर्प्रवाह के तुलना में सबल 7.9 बिलियन यूएस डॉलर था। (चित्र 22)

चित्र 21: निवल वार्षिक एफडीआई अंतर्वाह



डाटा स्रोत: आरबीआई मासिक बुलेटिन

चित्र 22: पूंजीगत अंतर्वाह की त्रैमासिक प्रवृत्ति



डाटा स्रोत: आरबीआई

1.32 देश के चालू खाते एवं उच्च पूंजीगत प्रवाह के सुधार के परिणामस्वरूप देश की भुगतान संतुलन (बीओपी) स्थिति में मार्च, 2019 के अंत का 302 बिलियन यूएस डॉलर के विदेशी विनिमय भंडार सुधार कर 10 जनवरी, 2020 में 461.2 बिलियन यूएस डालर हो गया है।

### क्षेत्रीय घटनाक्रम

1.33 सापेक्ष कीमतों के परिवर्तनों की अनुक्रिया, जिससे अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न दरों पर प्रगति होती है, में संसाधन क्षेत्रों में संचालित होते हैं। जीडीपी की ऊंची वृद्धि से प्रगति के क्षेत्रीय योगदान की ओर

ज्यादा ध्यान नहीं जाता, जितना कि जीडीपी की निम्न वृद्धि के दौरान जाता है। फिर भी, प्रगति के सभी स्तरों पर संरचनात्मक परिवर्तन है तथा यह परिवर्तन का काल है जो कि रुचि कर बन गया है।

1.34 देश के कुल जीवीए में कृषि एवं सहायक क्षेत्रों के अंश में वर्ष 2009-14 से 2014-19 तक गिरावट आई है, ऐसा मुख्यतः तीसरे क्षेत्र की सापेक्ष अधिक वृद्धि के कारण हुआ है। यह विकास प्रक्रिया की प्राकृतिक उपलब्धि है जिससे गैर कृषि क्षेत्रों में त्वरित प्रगति होती है।

तालिका 5: जीवीए में क्षेत्रीय अंश ( प्रतिशत )

	2009-10 to 2013-14	2014-15 to 2018-19	2018-19	H1: 2019-20
कृषि वन एवं मत्स्य	18.3	17.4	16.1	13.9
उद्योग	32.3	29.6	29.6	28.3
खनन एवं उत्खनन	3.2	2.4	2.4	2.1
विनिर्माण	17.5	16.6	16.4	15.4
विद्युत, गैस, जल आपूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवाएं	2.4	2.6	2.8	2.9
निर्माण	9.2	8.0	8.0	8.0
सेवाएं	49.4	52.9	54.3	57.8

व्यापार, होटल, यातायात, संग्रहण, ब्रॉडकास्टिंग से संबंधित संचार एवं सेवाएं	17.5	18.3	18.3	18.1
वित्तीय, रियल एस्टेट एवं व्यवसायिक सेवाएं	19.2	20.9	21.3	24.5
जन प्रशासन, रक्षा एवं अन्य सेवाएं	12.7	13.7	14.7	15.2

स्रोत: राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय

1.35 जीवीए के प्रति औद्योगिक क्रियाकलापों के योगदान में भी 2009-14 से 2014-19 तक की अवधि में कमी दर्ज की गई है। विनिर्माण सैक्टर जिसका औद्योगिक जीवीए में 50 प्रतिशत से अधिक का योगदान रहा है, के योगदान में कमी देखने को मिली है जबकि निर्माण क्षेत्र की भागीदारी भी कम रही है।

1.36 सेवा सैक्टर ने कृषि और उद्योग सैक्टर की अपेक्षा तेजी से प्रगति की है। वित्तीय, रियल इस्टेट और व्यावसायिक सेवाओं के सैक्टर ने लोक प्रशासन के बाद सेवा क्षेत्र के योगदान में वृद्धि दर्ज कराई है। यहां तक कि वैश्विक रूप में, उत्पादन क्षेत्र होने वाली गिरावट को आंशिक रूप से खत्म करके वैश्विक वृद्धि में योगदान दिया है।

### प्रथम अग्रिम प्रॉक्कलन 2019-20

1.37 प्रथम अग्रिम प्रॉक्कलन के अनुसार, 2019-20 के दौरान वास्तविक जीडीपी में 5.0 प्रतिशत वृद्धि होने का प्रॉक्कलन किया गया है जबकि 2018-19 में जीडीपी वृद्धि की दर 6.8 प्रतिशत दर्ज की गई थी। 2018-19 के लिए जीडीपी (190.1 लाख करोड़) के अनंतिम प्रॉक्कलन पर 7.5 प्रतिशत की वृद्धि दर के साथ 2019-20 में नामिक जीडीपी वृद्धि का प्रॉक्कलन 204.4 लाख करोड़ है।

1.38 चालू कीमतों पर जीडीपी में कुल उपभोग एवं निवल निर्यात के अंशदान में वर्ष 2018-19 की तुलना में वर्ष 2019-20 में वृद्धि होने का प्रॉक्कलन किया

तालिका 6: मांग पक्ष के घटक (जीडीपी के प्रतिशत के रूप में)

	2017-18	2018-19	2019-20	Percentage points change in share in 2019-20 over 2018-19
	1 <sup>st</sup> RE	PE	1 <sup>st</sup> AE	[Increase (+)/ Decrease (-)]
कुल खपत	70.0	70.6	72.1	1.5
सरकारी खपत	11.0	11.2	11.9	0.7
निजी खपत	59.0	59.4	60.2	0.8
सकल निर्धारित फोरनेशन	28.6	29.3	28.1	-1.2
कुल निर्यात	-3.2	-3.9	-2.8	1.1
माल एवं सेवाओं का निर्यात	18.8	19.7	18.4	-1.3
माल एवं सेवाओं का आयात	22.0	23.6	21.2	-2.4

स्रोत: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय

टिप्पणी: RE-संशोधित प्रॉक्कलन, PE-अनंतिम प्रॉक्कलन, AE-अग्रिम प्रॉक्कलन।



तालिका 7: जीवीए और जीडीपी की वृद्धि दर 2011-12 की स्थिर कीमतों पर,

	2017-18	2018-19	2019-20	Percentage points Change in growth in 2019-20 over 2018-19
	1 <sup>st</sup> RE	PE	1 <sup>st</sup> AE	[Increase (+)/ Decrease (-)]
<b>मूल मूल्यों पर जीवीए</b>	<b>6.9</b>	<b>6.6</b>	<b>4.9</b>	<b>-1.7</b>
कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र	5.0	2.9	2.8	-0.1
उद्योग	5.9	6.9	2.5	-4.4
खनन एवं उत्खनन	5.1	1.3	1.5	0.2
विनर्माण	5.9	6.9	2.0	-5.0
विद्युत, गैस, जल आपूर्ति एवं अन्य उपयोगिता सेवाएं	8.6	7.0	5.4	-1.6
निर्माण	5.6	8.7	3.2	-5.6
सेवाएं	<b>8.1</b>	<b>7.5</b>	<b>6.9</b>	<b>-0.7</b>
व्यापार, होटल, यातायात, संचार एवं संचार एवं प्रसारण संबंधित सेवाएं	7.8	6.9	5.9	-1.0
वित्तीय, रिएल एस्टेट एवं व्यवसायिक सेवाएं	6.2	7.4	6.4	-1.1
जन प्रशासन, रक्षा एवं अन्य सेवाएं	11.9	8.6	9.1	0.5
बाजार मूल्य पर जीडीपी	<b>7.2</b>	<b>6.8</b>	<b>5.0</b>	<b>-1.8</b>

स्रोत: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय

टिप्पणी: RE-संशोधित अनुमान, PE-अंतिम अनुमान, AE-अग्रिम अनुमान।

गया है। चालू कीमतों पर जीडीपी के प्रतिशत के रूप में अचल निवेश 2018-19 में 29.3 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2019-20 में 28.1 प्रॉक्कलित किया गया है।

1.39 2019-20 में मूल कीमतों पर वास्तविक जीवीए की वृद्धि 4.9 प्रतिशत अनुमानित है, जबकि वर्ष 2018-19 में यह 6.6 प्रतिशत थी। 'सार्वजनिक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाओं' को छोड़कर सभी उपक्षेत्रों में जीवीए वृद्धि में शिथिलता का आकलन किया गया है। (तालिका 7)

1.40 तालिका 8 में अर्थव्यवस्था के प्रमुख संकेतक दिखाए गए हैं। प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार 2018-19 में 6.8 प्रतिशत की वृद्धि दर की तुलना में 2019-20 के दौरान वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 4.8 प्रतिशत है। प्रथम अग्रिम अनुमान से लगता है कि एच1 2019-20 की तुलना में एच2 2019-20 में वृद्धि होगी, जिसके कारण नीचे दिए गए हैं:

पहला, निफ्टी इंडिया उपभोग सूचकांक पिछले महीनों की नकारात्मक वृद्धि की तुलना में पहली बार अक्टूबर, 2019 में 10.1 प्रतिशत की धनात्मक वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि के साथ इस वर्ष पहली बार सबसे ऊपर रहा। यह वृद्धि नवंबर, 2019 में 5.7 प्रतिशत तथा दिसंबर, 2019 में 0.2 प्रतिशत तक सकारात्मक बनी रही।

दूसरा, भारतीय अर्थनीति में सकारात्मक आत्मविश्वास को बहाल रखते हुए अनुषंगी बाजारों में भी बढ़ोतरी जारी रही तथा मुंबई स्टॉक एक्सचेंज सूचकांक में 31 मार्च, 2019 की तुलना में 7.0 प्रतिशत (31 दिसम्बर, 2019 तक) की वृद्धि हुई।

तीसरा, विदेशी निवेशकों ने भारत में विश्वास दिखाया है। देश ने अप्रैल-नवम्बर, 2018-19 में 21.2 यूएस बिलियन डॉलर के तुलना में अप्रैल-नवम्बर, 2019-20 में 24.4 बिलियन यूएस डॉलर की कुल एफडीआई को आकर्षित किया। अप्रैल-नवम्बर 2019-20 में कुल

तालिका 8: प्रमुख संकेतक

आंकड़ों की श्रेणियां	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
<b>जी डी पी और संबंधित संकेतक</b>					
चालू बाजार दर पर जी डी पी	₹ लाख करोड़	153.6	171.0	190.1 <sup>a</sup>	204.4 <sup>b</sup>
स्थिर बाजार दर पर जी डी पी	₹ लाख करोड़	123.0	131.8	140.8 <sup>a</sup>	147.8 <sup>b</sup>
वृद्धि दर	(प्रतिशत)	8.2	7.2	6.8 <sup>a</sup>	5.0 <sup>b</sup>
चालू आधार कीमत पर जी वी ए	₹ लाख करोड़	139.4	154.8	172.0 <sup>a</sup>	185.0 <sup>b</sup>
स्थिर आधार कीमत पर जी वी ए	₹ लाख करोड़	113.2	121.0	129.1 <sup>a</sup>	135.4 <sup>b</sup>
वृद्धि दर	(प्रतिशत)	7.9	6.9	6.6 <sup>a</sup>	4.9 <sup>b</sup>
सकल बचत	% जी डी पी	30.3	30.5	na	na
सकल पूंजीगत निर्माण	% जी डी पी	30.9	32.3	na	na
प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय आय (चालू कीमत पर)	₹	104659	114958	126406 <sup>a</sup>	135050 <sup>b</sup>
<b>उत्पादन</b>					
खाद्यान्न	मिलियन टन	275.1	285.0	285.0 <sup>c</sup>	140.6 <sup>c</sup>
औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक	(प्रतिशत)	4.6	4.4	3.8	0.6 <sup>d</sup>
विद्युत सृजन (वृद्धि)	(प्रतिशत)	4.7	4.0	3.5	0.3 <sup>d</sup>
<b>कीमत</b>					
डब्ल्यू पी आई औसत	(प्रतिशत)	1.7	3.0	4.3	1.5 <sup>e</sup>
सी पी आई (संयुक्त) मुद्रास्फिति (औसत)	(प्रतिशत)	4.5	3.6	3.4	4.1 <sup>e</sup>
<b>वैदेशिक क्षेत्र</b>					
व्यापारिक माल निर्यात वृद्धि (\$यू एस के संदर्भ में)	(प्रतिशत)	5.2	10.0	8.8	-2.0 <sup>e</sup>
व्यापारिक माल निर्यात वृद्धि (\$यू एस के संदर्भ में)	(प्रतिशत)	0.9	21.1	10.4	-8.9 <sup>e</sup>
चालू खाता कोष	% जी डी पी	-0.6	-1.8	-2.1	1.5 <sup>f</sup>
विदेशी विनिमय आरक्षण निधि (वर्षांत)	US\$ Billion	370.0	424.5	412.9	457.5 <sup>j</sup>
औसत विनिमय दर	₹ /US\$	67.1	64.5	69.9	70.4 <sup>e</sup>
<b>धन और ऋण</b>					
व्यापक मुद्रा (एम3) वृद्धि (वार्षिक)	(प्रतिशत)	10.1	9.2	10.5	9.8 <sup>g</sup>
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक ऋण (वृद्धि)	(प्रतिशत)	8.2	10.0	13.3	7.2 <sup>g</sup>

आंकड़ों की श्रेणियां	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
<b>राजकोषीय संकेतक ( केन्द्र )</b>					
संकल राजकोषीय घाटा	% जी डी पी	3.5	3.5	3.4 <sup>h</sup>	3.3 <sup>i</sup>
राजस्व घाटा	% जी डी पी	2.1	2.6	2.2 <sup>h</sup>	2.3 <sup>i</sup>
प्राथमिक घाटा	% जी डी पी	0.4	0.4	0.2 <sup>h</sup>	0.2 <sup>i</sup>

टिप्पणी: उपलब्ध नहीं

क. अनंतिक आकलन

घ. (अप्रैल-नवम्बर) 2019

छ. नवंबर 2019

अ. दिसंबर 2019 का अंत

ख. प्रथम अग्रिम आकलन

ड. (अप्रैल-दिसंबर) 2019

ज. संशोधित अनुमान

ग. 2018-19 का प्रथम ए. ई. तथा 2019-20 का प्रथम ए. ई.

च. (अप्रैल-सितंबर) 2019

अ. बजट अनुमान

एफपीआई उल्लेखनीय 12.6 बिलियन यूएस डॉलर थी जबकि अप्रैल-नवम्बर 2018-19 में तो 8.7 बिलियन यूएस डॉलर का बहिर्वाह हुआ था।

चौथा, रेपो दर में पिछली कटौती का प्रभाव बढ़ते मांग दबाव को दर्शाता है। सीपीआई कोर मुद्रास्फीति अक्टूबर, 2019 में 3.4 प्रतिशत से नवंबर, 2019 में 3.6 प्रतिशत बढ़ी है। इसके अतिरिक्त दिसम्बर, 2019 में 3.8 प्रतिशत। डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति अक्टूबर, 2019 में 0 प्रतिशत से नवंबर, 2019 में 0.6 प्रतिशत बढ़ी है, तथा दिसम्बर 2019 में 2.6 प्रतिशत।

पांचवा, किसान के लिए व्यापार की शर्तों में सुधार हो रहा है जो ग्रामीण उपयोग को बढ़ाएगा। खाद्य स्फीति अप्रैल, 2019 से बढ़ रही है।

छठा, औद्योगिक गतिविधि प्रतिक्षेप पर है तथा सुधार का संकेत दे रही है। अक्टूबर, 2019 में 3.4 प्रतिशत तथा सितंबर 2019 में 4.3 प्रतिशत की कमी की तुलना में नवम्बर, 2019 में आईआईपी ने 1.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज कराई है। आईआईपी के साथ-साथ, आठ मुख्य उद्योग अक्टूबर, 2019 में 5.8 प्रतिशत के अन्तर्विरोध की तुलना में नवम्बर, 2019 में 1.5 प्रतिशत का कम अन्तर्विरोध दर्ज करते हुए बहाली का संकेत दे रहे हैं। यह व्यापार चक्र के साथ सुसंगत है।

सातवां, पीएमआई विनिर्माण ने अक्टूबर, 2019 में 50.6 से नवंबर में 51.2 तथा दिसम्बर 2019 में 52.7 का बढ़ता हुआ स्थायी सुधार किया है। पीएमआई सेवाएं

नवम्बर, 2019 में 52.7 (अक्टूबर 2019 में 49.2 से) तथा अतिरिक्त दिसम्बर, 2019 में 53.3 तक बढ़ी है।

आठवां, व्यापारिक निर्यात में वृद्धि में, जैसा कि दिखाई देता है, 2019-20 की तीसरी तिमाही में 0.8 प्रतिशत की गिरावट की तुलना में सुधार हुआ है जो कि 2019-20 की दूसरी तिमाही में 3.7 प्रतिशत की गिरावट की तुलना में कम है। तदनुसार जीडीपी वृद्धि के लिए निर्यात की प्रेरणा बढ़ने की आशा है। 2019-20 के प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार, जीडीपी की वृद्धि में कुल निर्यात 2018-19 में 1.1 प्रतिशत के बिन्दु से बढ़ने का अनुमान है।

नौवां, फोरेक्स रिजर्व मार्च 2019 के अन्त में 413 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 10 जनवरी, 2020 में 461.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक आ गया है। यह भारत की अर्थव्यवस्था में बाहरी निवेशकों के बढ़ते हुए विश्वास को दिखाता है।

दसवां, सितम्बर तथा अक्टूबर 2019 में नकारात्मक वृद्धि दर दर्ज कराने के बाद पूर्व वर्ष के समान मास में दिसम्बर 2019 तथा नवम्बर 2019 में एकत्र किया गया सकल जीएसटी राजस्व ने क्रमशः 9 प्रतिशत तथा 6 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर दर्ज की है। अप्रैल-दिसम्बर 2019, के दौरान संग्रहित सकल जीएसटी राजस्व ने बढ़ती हुए संपूर्ण आर्थिक गतिविधि की ओर इंगित करते हुए पांचवी बार 1 लाख करोड़ रु. के आंकड़े को पार कर दिया है।

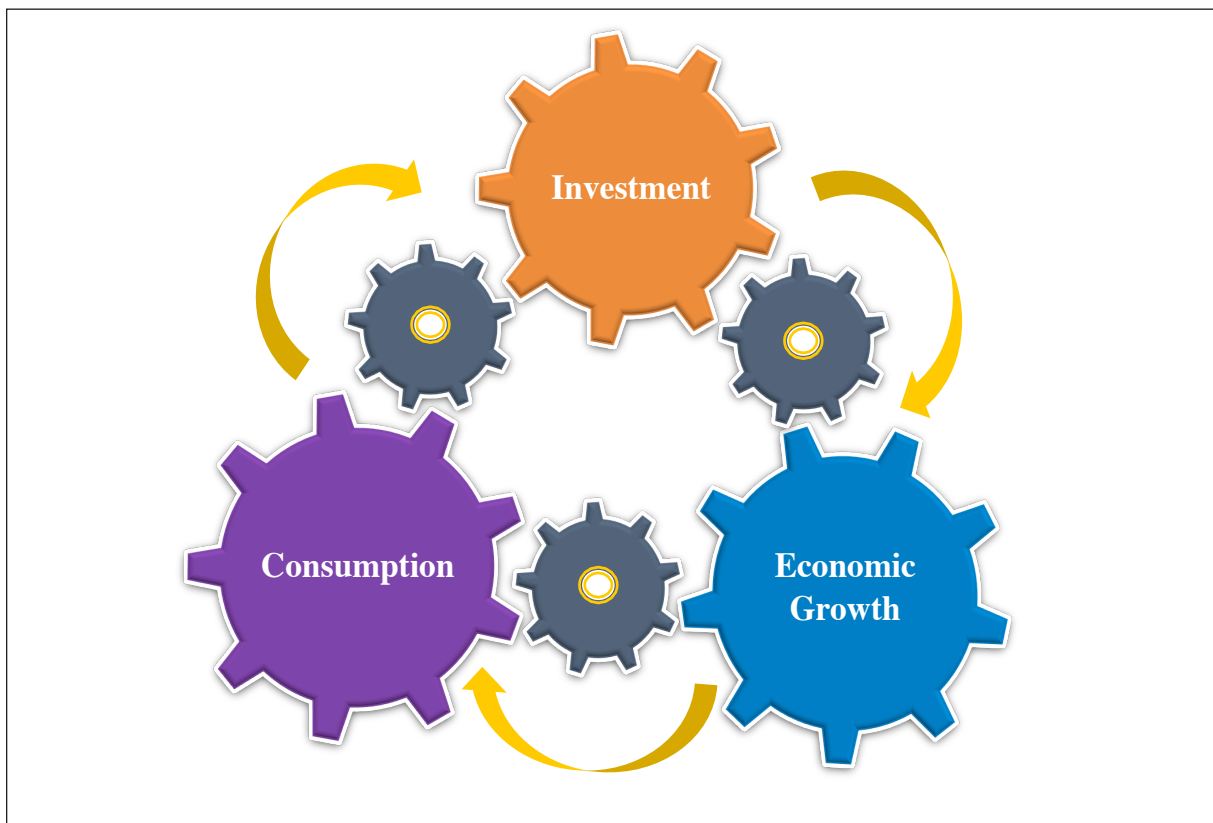
## वृद्धि में हालिया कमी: वास्तविक क्षेत्र पर वित्तीय क्षेत्र द्वारा अवरोध

### वृद्धि का मंदन चक्र

1.41 आर्थिक समीक्षा 2018-19 वृद्धि के सुचक्र को भलीभांति चित्रित करती है जिसमें अचल निवेश की दर में वृद्धि जीडीपी की वृद्धि को तेज करती है

जो उपभोग को अपेक्षाकृत उच्च वृद्धि की ओर प्रवृत्त करती है। उपभोग में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि से निवेश परिदृश्य विस्तार को प्राप्त करता है, जो क्रमिक रूप से फिर अचल निवेश में परिणत हो जाता है और जीडीपी वृद्धि को तेज करता है तथा उपभोग में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि को प्रेरित करता है। अपेक्षाकृत अधिक अचल निवेश के अच्छे परिणाम-उच्च

चित्र 23: संवृद्धि का सुचक्र



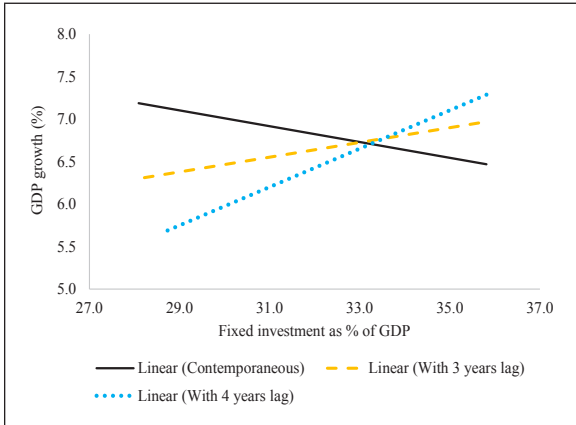
जीडीपी वृद्धि (चित्र 23) से देश में आर्थिक विकास होता है।

1.42 विलोमत: जब यह अच्छा चक्र धीमे घूमता है, तो अचल निवेश में कमी से जीडीपी वृद्धि, उपभोग वृद्धि में भी कमी आती है। भारत के मामले में अचल निवेश की दर और जीडीपी वृद्धि के बीच इस कम होते प्रभाव को 3 से 4 वर्ष तक देखा जा सकता है। (चित्र 24)। इसी प्रकार उपभोग वृद्धि पर जीडीपी

वृद्धि का प्रभाव एक से दो वर्ष में परिलक्षित होता है। (चित्र 25)। अतएव दोनों के बीच नकारात्मक सह संबंध को देखते हुए जीडीपी वृद्धि और निवेश की समकालिक तुलना सही नहीं है।

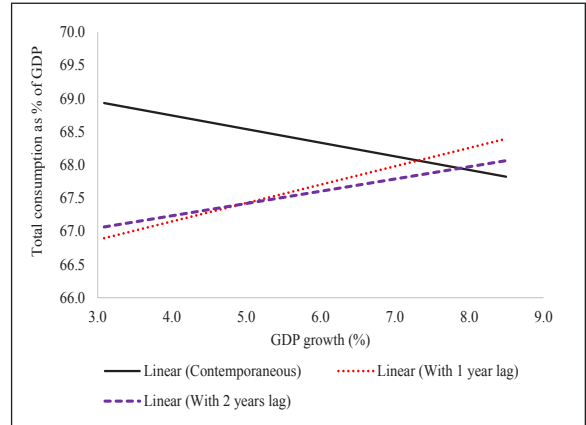
1.43 भारतीय अर्थव्यवस्था 2011-12 से विकास के चक्र के धीमेपन के प्रभाव को दर्शा रही है। अचल विदेश दर 2011-12 से तीव्र गति से गिरना शुरू

**चित्र 24: संवृद्धि पर निवेश का विलंबित प्रभाव ( 2004-2008 )**



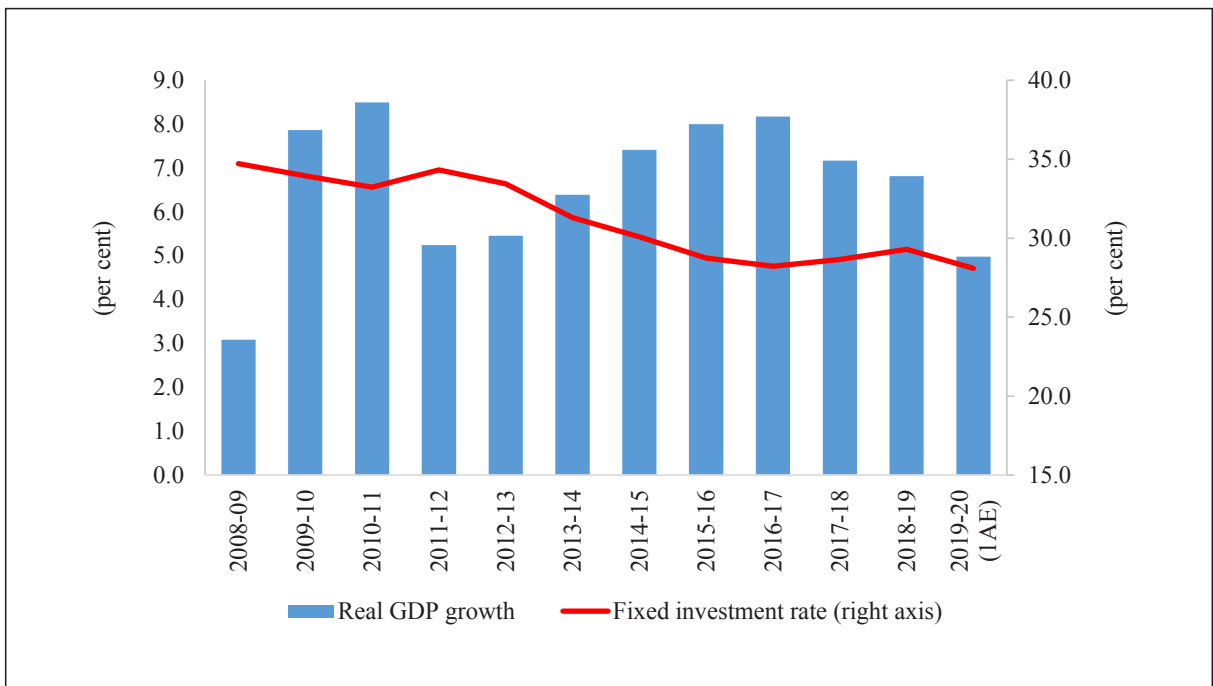
आंकड़ा स्रोत: राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय

**चित्र 25: उपभोग पर संवृद्धि का विलंबित प्रभाव ( 2004-2009 )**



आंकड़ा स्रोत: राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय

**चित्र 26: वास्तविक जीडीपी संवृद्धि और निवेश वर्षानुगत परिवर्तन**



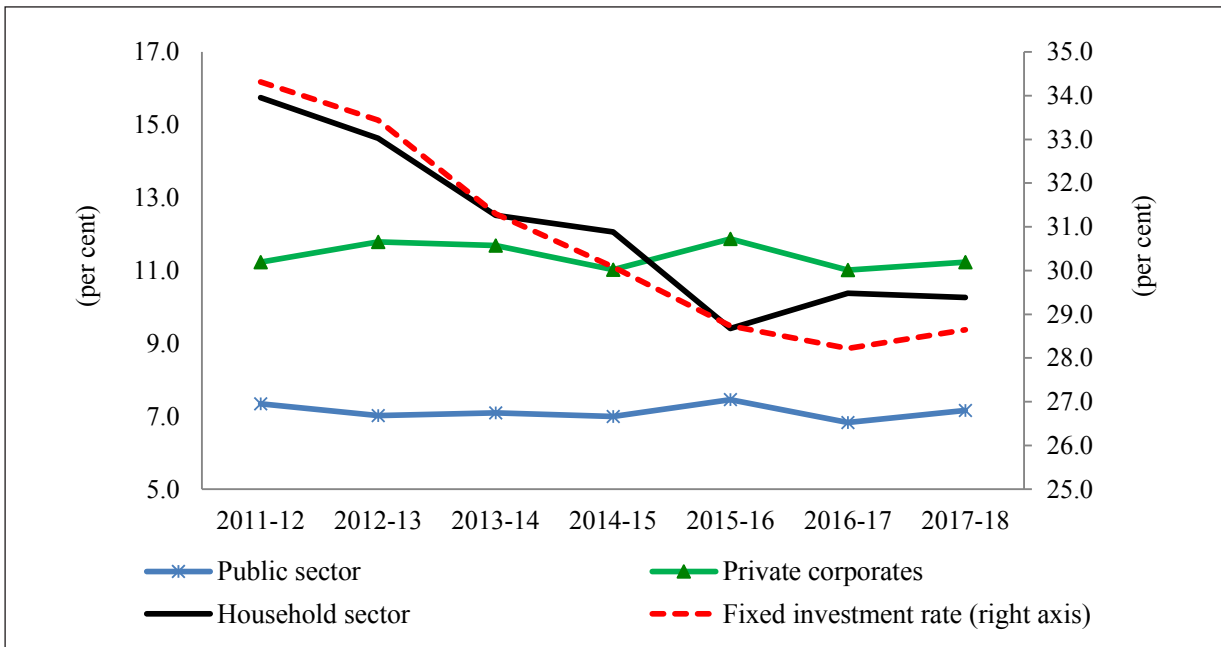
डाटाबेस: राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय

हो गई है। और 2016-17 के बाद से यह कभी स्थायितवपूर्ण हुई है। चित्र 24 में (शीर्ष गए निवेश दर के जीडीपी वृद्धि पर विलंबित प्रभाव [यह प्रभाव 4 वर्ष के बाद ही सबसे प्रबल होता है] को देखते हुए संवृद्धि में 2017-18 से प्रारंभ मंदन हमारी उपर्युक्त रूपरेखा के अनुरूप ही है (चित्र 26)।

**अचल निवेश दर में कमी**

1.44 2009-14 से 2014-19 (चित्र 27) के बीच समग्र अचलनिवेश में गिरावट अधिकतर परिवारों द्वारा अचल निवेश 14.3 प्रतिशत से 10.5 प्रतिशत तक कमी के कारण आई है। निजी क्षेत्र में आंशिक रूप से अचल निवेश दो अवधियों के दौरान जीडीपी के

चित्र 27: संस्थागत क्षेत्र द्वारा अचल निवेश ( जीडीपी के प्रतिशत के अनुसार )



आंकड़ा स्रोत: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय

7.2 प्रतिशत से घटकर 7.1 प्रतिशत हो गया। तथापि, 2011-12 से 2017-18 के बीच लगभग जीडीपी के 11.5 प्रतिशत पर यह निजी कॉर्पोरेट निवेश में उहराव संवृद्धि धीमा चक्र को दर्शाता करने में एक गंभीर भूमिका दर्शाता है।

**निजी कॉर्पोरेट निवेश पर वित्तीय क्षेत्र का अवरोध**

1.45 कॉर्पोरेट निवेश में गिरावट को तर्कपूर्ण बनाने के लिए वित्तीय क्षेत्रों से जुड़े मुद्दों पर विचार करते हुए हमें ऋण में उछाल (मियां एव सूफी, 2018) को समझना चाहिए। अब यह अच्छी तरह समझ ली गई है कि अकस्मात ऋण विस्तार तो कि पूरी तरह पूर्ति प्रेरित है। इसके परिणामस्वरूप अल्पकालिक उत्पादन और रोजगार वृद्धि हो सकती है लेकिन दीर्घावधि में ये महत्वपूर्ण रूप से सिकुड़ जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (2017) में इस संबंध का 80 देशों में देखा गया। इन सभी मामलों में ऋण चैनल घरेलू ऋण के माध्यम से कार्य करता है यहां घरेलू ऋण की मांग में लघु अवधि के लिए वृद्धि होती है और यह मांग अगले चरण (फेज) में कम हो गई जिसके परिणाम स्वरूप मंदी आई।

1.46 भारतीय परिदृश्य में ऋण चैनल कॉर्पोरेट निवेश के माध्यम से कार्य करता है उभार के बाद तेजी

कॉर्पोरेट क्षेत्र में लाभोपरान्तक और निम्न निवेश का चित्रण किया गया, जो कि धीरे-धीरे जीडीपी वृद्धि में हाल ही की गिरावट का कारण रही। यहां पर यह कहना उपयोगी होगा कि वृद्धि के कम होने के चक्र का मूल 2000 के वर्षों मध्य तथा उसके बाद अधिक ऋण उछाल में निहित है जब गैर खाद्य बैंक ऋण प्राय 2003-04 से 2007-08 के बीच तीन गुना हो गए तथा 2007-08 से 2011-12 के बीच दो गुना हो गए थे। क्या यह संभव है कि उछाल अवधि के दौरान अतार्किक तरीके से अधिक बैंक उधार हो गया, जिससे भविष्य में कॉर्पोरेट निवेश में कमी आई हो।

1.47 इस घटनाक्रम पर समुचित साक्ष्य की दृष्टि से किसी फर्म के ऋण विस्तार और इसके भावी निवेश के बीच संघ संबंध की जांच की जाती है। मियां और सूफी (2018) की विधि के अनुसरण में डाटा फर्म-वर्ष स्तर पर संमोजित किया जाता है निश्चित वर्ष के लिए परिवर्तन आधारित वृद्धि वस्तुतः निवेश में वृद्धि है-वर्ष टी से टी +4 तथा स्पष्ट परिवर्तन टी-5 से टी-1 के दौरान ऋण का विस्तार है। उदाहरण के लिए वर्ष 2012 में निवेश वृद्धि 2011-12 के बीच निर्धारित परिसंपत्ति में अंतर और कुल 2006-07 के बीच कुल परिसंपत्ति

अनुपात की तुलना में ऋण अंतर है। कुल पांच वर्षों में प्रत्येक निश्चित वर्ष के लिए (2011-2015) निर्भर चर का व्याख्या चर पर के क्रास-सेक्शन प्रतीपमगमन किया गया है। दोनों के बीच संबंध की सांख्यिकीय महत्ता को नीचे सूचीबद्ध किया गया है। (तालिका 9)

1.48 निर्णायक रूप से, हम यह उल्लेख करते हैं कि वर्ष 2013 के लिए, यह संबंध नकारात्मक और सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण दोनों प्रकार का है। इसका निहितार्थ है कि जिन फर्मों ने 2007-08 से वर्ष 2011-12 की अवधि के बीच अतिरिक्त उधार लिया था, वस्तुतः वर्ष 2012-13 से वर्ष 2016-2017 की अवधि के दौरान अत्यधिक कम निवेश पायीं चूंकि यह परिणाम किसी अन्य पंचवर्षीय

अवधि के लिए सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण होता है, इसलिए वर्ष 2013 निवेश पर ऋण (क्रेडिट) बाहुल्यता के निवेश पर प्रभाव की व्याख्या करने में यह निर्णायक बन जाता है। वस्तुतः, वर्ष 2013 विश्लेषण में निर्णायक (केन्द्र बिन्दु) होने से निवेश दर में बड़े पैमाने पर गिरावट के साथ उपर्युक्त प्रवृत्ति चित्र 26 में देखी गई है।

1.49 वर्ष (2007-08) जब फर्मों ने अत्यधिक उधर लेना शुरू किया, वही वर्ष था जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक ने लगभग सभी ऋणों के लिए विनियामक स्थगन (बैंकों द्वारा ऋणों की भुगतान अनुसूची पुनः बनाने के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के विवेकपूर्ण दिशा निर्देश 27, अगस्त, 2008) लागू किया गया था। यह प्रतीत

**तालिका 9: ऋण वृद्धि और निवेश के बीच संबंध**

फर्म वर्ष	ऋण वृद्धि (ऋण/परिसंपदा अनुपात में वृद्धि)	निवेश (अचल परिसंपदाओं में वृद्धि)	संबंध
2011	2006-10	2011-15	महत्वपूर्ण नहीं
2012	2007-11	2012-16	महत्वपूर्ण नहीं
2013	2008-12	2013-17	महत्वपूर्ण और नकारात्मक
2014	2009-13	2014-18	महत्वपूर्ण नहीं
2015	2010-14	2015-19	महत्वपूर्ण नहीं

होता है कि जो फर्म अतिरिक्त ऋण लेने की लाभार्थी फर्म थी, उनको विनियामक स्थगन की सुविधा प्रदान की गई, उनके बारे में यह प्रतीत होता था कि अधिकांश उन फर्मों ने निवेश में कटौती कर दी। संभवतः, लाभार्थी फर्म वे फर्म थीं जिन्होंने पर, उनके उच्चतर ऋण के कारण, नई परिसंपदाओं में निवेश करने के बजाय, लाभ न उठाने (डिविदरेजिंग) पर अधिक ध्यान दिया था।

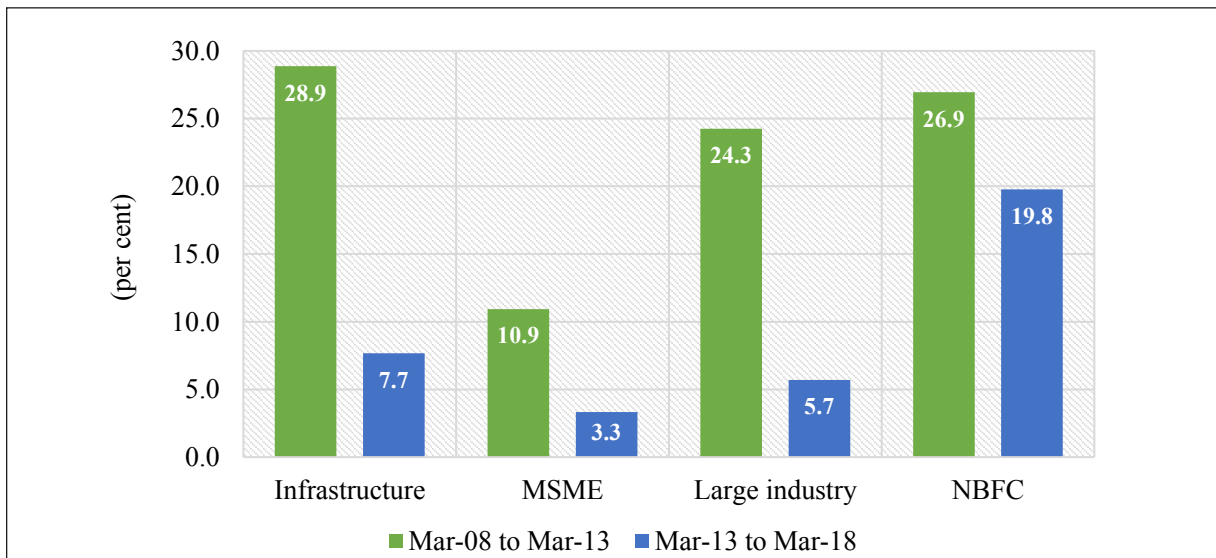
1.50 ऋण में उछाल के बाद बैंकों की ऋण वृद्धि में गिरावट आना प्रारंभ हुआ। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए गैर खाद्य ऋण की वृद्धि वर्ष 2009-14 की अवधि में 16.7 प्रतिशत से लुढ़क कर वर्ष 2014-19 की अवधि में 10.5 प्रतिशत रह गई। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की गैर खाद्य ऋण की वृद्धि में गिरावट के बाद बैंकों की गैर निष्पादक परिसंपत्तियों (एनपीए में

वृद्धि वर्ष 2009-14 की अवधि में कुल ऋणों के 3.0 प्रतिशत के औसत से बढ़कर वर्ष 2014-19 की अवधि में 8.3 प्रतिशत हो गई। बड़ी इकाइयों सूक्ष्म, लघु मध्यम उद्यमों की अवसंरचना के लिए और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के लिए भी बैंक ऋण वृद्धि में वर्ष 2009-14 की अवधि की तुलना में वर्ष 2014-19 की अवधि के दौरान काफी गिरावट आई (चित्र 28)

**घरेलू निवेश में कमी**

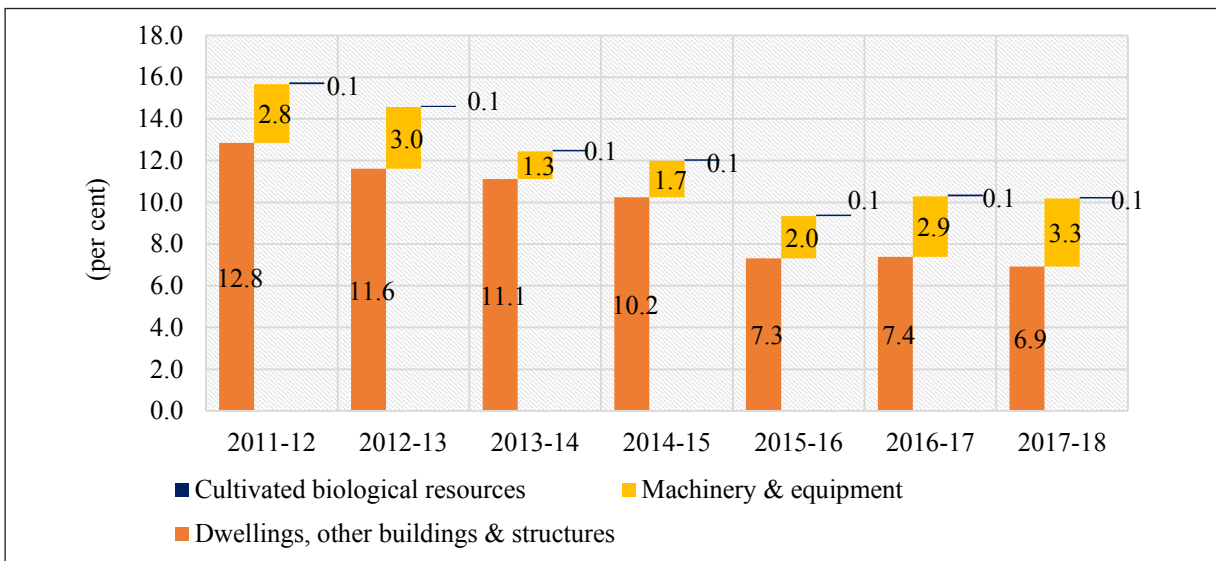
1.51 पारिवारिक क्षेत्र में परिवारों के साथ-साथ ‘अर्ध-निगम’ भी शामिल हैं। घरों से संबंधित असबद्ध उद्यम, जिसमें उनका संपूर्ण विवरण होता है, उन्हें ‘अर्ध-निगम’ कहा जाता है। घरेलू क्षेत्र के निवेश का टूटना दर्शाता है कि ‘मशीनरी और उपकरण’ तथा ‘अन्य

चित्र 28: विभिन्न क्षेत्रों में क्रेडिट (साख) में वृद्धि



डाटा स्रोत: आरबीआई

चित्र 29: परिसंपत्ति द्वारा घरेलू नियत निवेश (जीडीपी के प्रतिशत अनुसार)



डाटा स्रोत: राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय

इमारतों और संरचनाओं' के निवेश में कुल घरेलू क्षेत्र के निवेश का दो-तिहाई से अधिक हिस्सा होता है।

1.52 खुदरा उपभोग के लिए सीधे आपूर्ति करने के अलावा, घरों से संबंधित अनियमित उद्यम मूल्य श्रृंखला के पिछले छोर से शामिल उद्यमों के लिए आपूर्तिकर्ता हैं। वर्ष 2011-12 से 2017-18 (चित्र 29) तक जीडीपी के प्रतिशत के रूप में घरों के मशीनरी और

उपकरण संबंधित निवेश में गिरावट संभवतया इसी अवधि के दौरान निजी कॉर्पोरेट निवेश के स्तर से जुड़ी हुई हो सकती है।

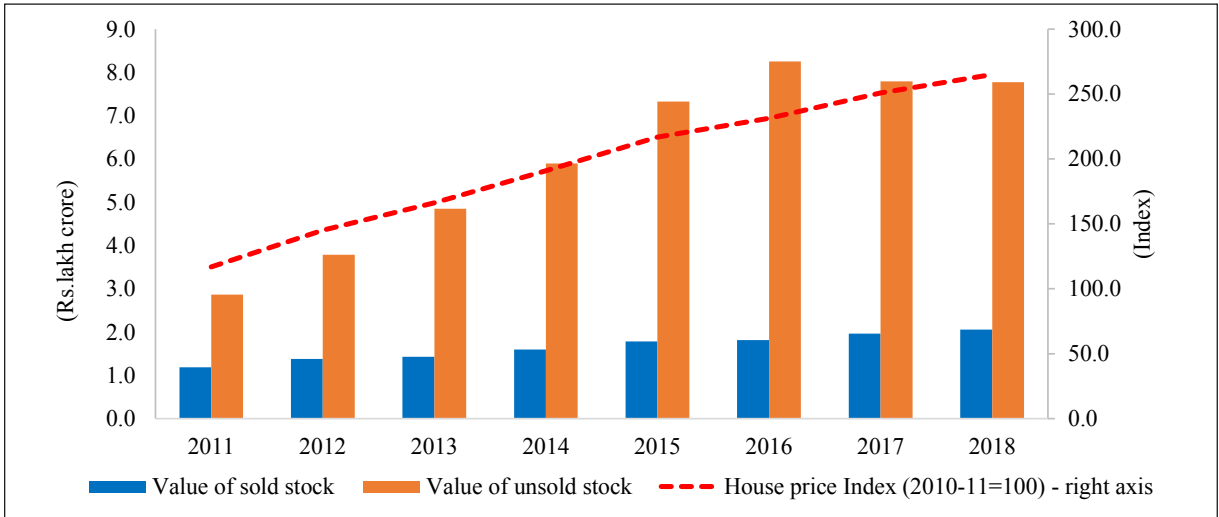
1.53 वर्ष 2011-12 से 2017-18 के दौरान 'आवास, अन्य भवनों और संरचनाओं' में घरेलू निवेश में गिरावट लोगों द्वारा मकानों के क्रय में धीमी वृद्धि का परिलक्षण है। रीयल इस्टेट क्षेत्र और, विशेष रूप से आवासीय



संपत्ति, क्षेत्र विलंबित परियोजना परिदान संबंधी मुद्दों और अटकी हुई परियोजनाओं के कारण डगमगाने की स्थिति में रहे हैं जिसके कारण विगत वर्षों के दौरान अविक्रीत मकानों की संख्या बढ़ी है। वर्ष 2015-16 की प्रथम तिमाही से तेजी से गिरावट होने के बावजूद भी कीमतें ऊंची बनी रही हैं और इस क्षेत्र में तभी से

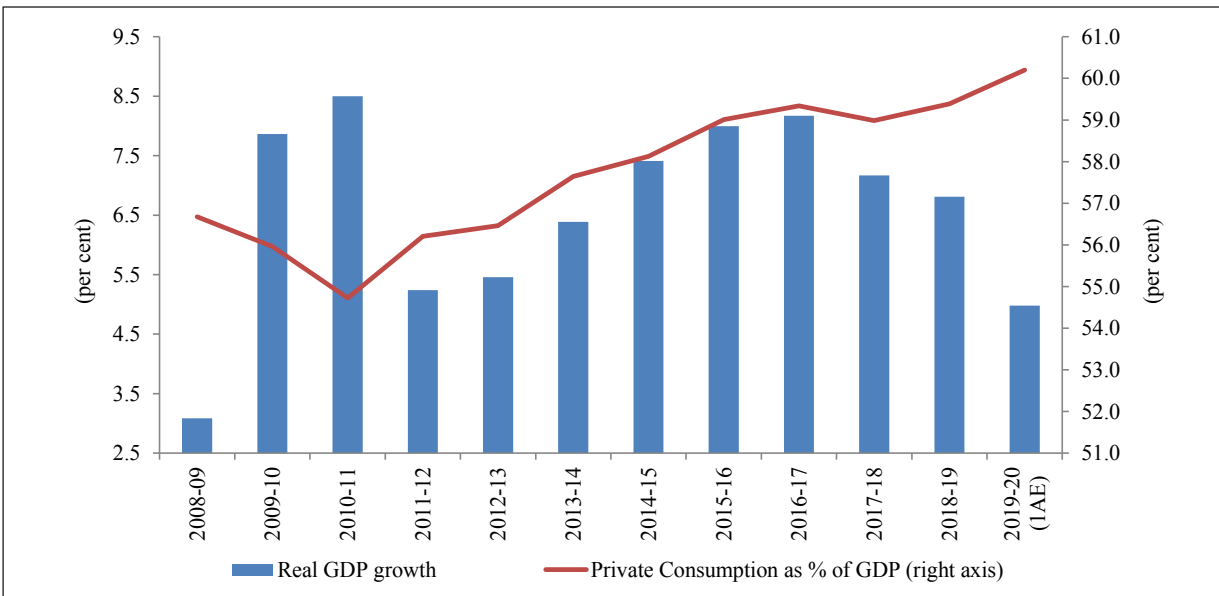
मंदी की स्थिति बनी हुई है। दिसंबर 2018 के अंत में, 8 शीर्षस्थ शहरों में 41 माह के स्टॉक के रूप में ₹ 7.77 लाख करोड़ रुपए कीमत की लगभग 9.43 लाख इकाईयां (मकान), परियोजना चक्र में विभिन्न चरणों में अटकी पड़ी हैं (चित्र 30)

**चित्र 30: मकानों के बिना बिके स्टॉक, विक्रय और कीमत सूचकांक**



डाटा स्रोत: लायसेज फोरस (2019), आरबीआई  
टिप्पणी: वर्ष यहां पर कैलेंडर वर्ष है।

**चित्र 31: वास्तविक जीडीपी वृद्धि और निजी उपभोग ( जीडीपी के प्रतिशत के रूप में )**



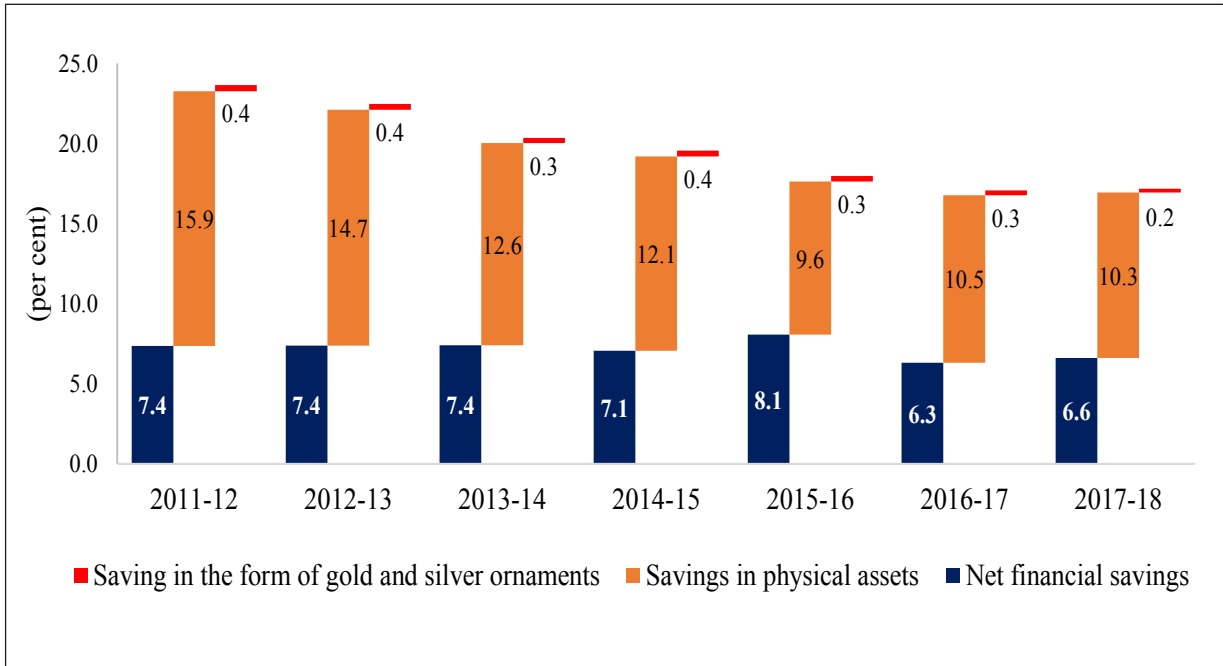
स्रोत: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय

**निजी उपभोग में बिलंबित गिरावट**

1.54 निजी वृद्धि में वर्ष 2009 से 16 तक, विशेषकर वर्ष 2014-16 में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के अनुपात में वृद्धि हुई है (चित्र 31)। इसके बाद इसमें वर्ष 2017-18 में कमी आई और वर्ष 2019-20 के

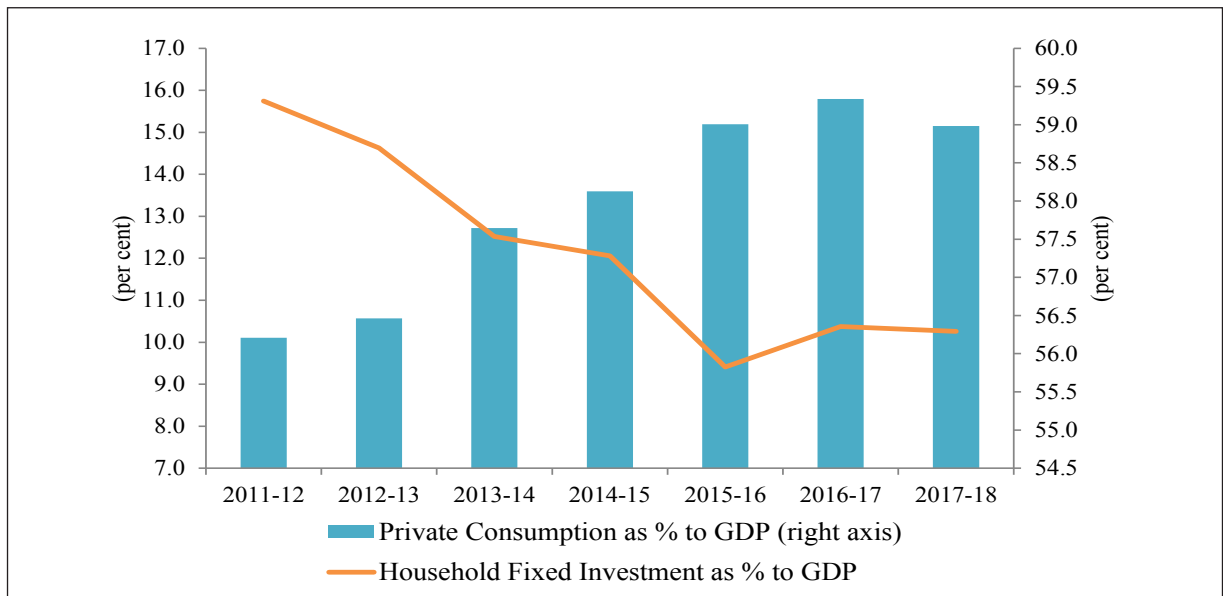
प्रथम छमाही (एच1) में तेजी से कमी आने से पहले वर्ष 2018-19 में पुनः इसमें वृद्धि हुई। चित्र 25 में दर्शाए गए अनुसार 1-2 वर्ष की अवधि के बाद उपभोग पर सकल घरेलू उत्पाद का प्रभाव कई गुणा हो गया। इसलिए वर्ष 2017-18 से उपभोग में गिरते हुए रूझान

**चित्र 32: परिसंपत्ति किस्म द्वारा पारिवारिक बचत (जीडीपी के प्रतिशत के अनुसार)**



डाटा स्रोत: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय

**चित्र 33 घरेलू अचल निवेश और निजी उपभोग (जीडीपी की प्रतिशत के अनुसार)**



डाटा स्रोत: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय

पर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि में आंशिक गिरावट का प्रभाव प्रतिबिंबित होता है।

1.55 घरेलू निवेश में परिवर्तन से वर्ष 2016-17 तक की अवधि में उपभोग में वृद्धि हुई (चित्र 32)। इस अवधि के दौरान परिवारों की भौतिक परिसंपदाओं में की जाने वाली बचतों में गिरावट देखी गई है (चित्र)। जिस आय की बचत परिवारों द्वारा भौतिक परिसंपदाओं में नहीं की जाती है वह बचत या तो कीमती वस्तुओं (सोना-चांदी) के रूप में या निवल घरेलू वित्तीय बचतों के रूप में की जाती है या फिर उसका उपभोग किया जाता है। वर्ष 2011-12 से 2016-17 के दौरान जब भौतिक परिसंपदाओं में बचत में गिरावट हुई तब जीडीपी के समानुपात में, वृद्धि न तो सोने चांदी और न ही घरेलू वित्तीय बचतों के रूप में की गई। इस प्रकार, प्रतीत होता है कि वर्ष 2011-12 के बाद परिवारों द्वारा भौतिक परिसंपदाओं पर खर्च नहीं किए गए संसाधनों को अधिकांशतः उपभोग पर खर्च किया गया।

### संभावनाएं

1.56 जनवरी 2020 के अद्यतन में आईएमएफ ने 2020-21 में 5.8 प्रतिशत दर पर भारत में जीडीपी की वास्तविक वृद्धि का पूर्वकलन किया है। विश्व बैंक ने जनवरी 2020 में वैश्विक संभावनाओं में भी भारत की वास्तविक जीडीपी को 2020-21 में 5.8 प्रतिशत दर पर बढ़ते देखा है।

1.57 2019-20 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि के प्रथम अग्रिम अनुमान पर आधारित, 2019-20 के एच2 पर जीडीपी वृद्धि में समान वर्ष की पहली छमाही की तुलना में वृद्धि की उम्मीद है 2020-21 के बाद इसमें वृद्धि होने की संभावना है। जीडीपी में सभावित वृद्धि का आकलन करने के उद्देश्य से हम जीडीपी विकास में आकस्मिक तेजी लाने के लिए नकारात्मक और सकारात्मक दोनों जोखिम पर विचार करते हैं।

### नकारात्मक जोखिम

- विश्व व्यापार तनाव में निरंतर वृद्धि से वैश्विक उत्पादन वृद्धि के सुधार में देरी हो सकती है

जो देश के निर्यात निष्पादन को बाधित करेगा। कमजोर निर्यात वृद्धि अर्थव्यवस्था में अचल निवेश दर को बढ़ाने की लालसा को कम कर सकती हैं।

- भू-राजनीतिक तनाव में और अधिक वृद्धि से कच्चे तेल की कीमत बढ़ेगी तथा रुपए में गिरावट आएगी। निवल एफपीआई प्रवाह कम हो सकता है परिणाम स्वरूप रुपए पर और दबाव पड़ने से मूल्यहास हो सकता है। कच्चे तेल की मंहगाई उपभोक्ता तक पहुंचाने की अनुमति दी जाती है तो यह अर्थव्यवस्था में स्फीतिकारी दबाव बना देगा जिससे निजी उपभोग की वृद्धि घट जाएगी और निवेश करने की लालसा की कमजोर होगी। यहां तक कि यदि यह आंशिक भी होती है तो राजकोषीय घाटा तेज हो जाएगा जो जी-सेक्रेड पर प्रतिप्राप्ति बढ़ेगी तथा पूंजी की लागत में वृद्धि होगी, जो फिर से निवेश करने की लालसा को कम कर देगी।
- उन्नत देशों में विकास बहुत ही कम मुद्रास्फीति के साथ कमजोर हुआ है। पारंपरिक मौद्रिक नीति अपनी चरम सीमा पर है। मात्रात्मक आवरण घटाने पर चर्चा चल रही है जो मुद्रास्फीति को बढ़ावा दे सकता है और वास्तविक ब्याज दर को कम कर सकता है। भविष्य में किसी बिंदु पर मुद्रास्फीति को रोकने के लिए सेंट्रल बैंक द्वारा अल्पकालिक ब्याज दर बढ़ाई जा सकती है। इसके परिणाम स्वरूप भारत सहित उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं से पूंजी पलायन हो सकती है। आयात को मंहगा करने के लिए रुपया फिर से दबाव में आ जाएगा। आय के घरेलू चक्र प्रवाह से रिसाव बढ़ेगा जो निजी उपयोग तथा निवेश पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। अगर इसके बदले में उन्नत देशों में राजकोषीय विस्तार नीति का चुनी जाती है तो अल्पकालिक ब्याज दरों में वृद्धि पहले से अधिक होगी तथा भारत सहित ईएमई में आकस्मिक वृद्धि कमजोर होगी।

- आईबीसी कोड का कार्यान्वयन धीमी प्रगति पर है। जब तक इसमें प्रगति नहीं होगी बैंकों का आगे ऋण देने की जोखिम कम नहीं हो सकता। जोखिम प्रीमियम अधिक रहेगा और रेपो दरों में कटौती के बावजूद ऋण पर ब्यास दरों में कमी नहीं होगी। इसलिए निजी निवेश मंद रह सकता है।
- 102 लाख करोड़ रुपए की राष्ट्रीय निवेश योजना के घोषणा के पश्चात् निजी क्षेत्र में निवेश बढ़ने की उम्मीद है। यदि इससे राजकोषीय घाटे का विस्तार होता है तो बाँड प्रतिफल बढ़गी जिससे निजी निवेश बढ़ेगा। यदि इसके बदले निजी निवेश बाह्य फंडिंग की मांग करता है तो चालू खाता घाटा व्यापक रूप से कम हो जाएगा और इसकी वजह से उपयोग निवेश और संवृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगी।
- यदि सुधारों के साथ उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं होगी तो यह आर्थिक संवृद्धि को बढ़ावा देने के लिए स्थिर निवेश दर की आवश्यकता को बढ़ाएगा।
- सकल घरेलू बचत दरों की वृद्धि ही नदर सीएडी को खराब करेगी, लाएगी। रुपए में गिरावट और सुचक्र की प्राप्ति कठिन बना देगी।

### सकारात्मक जोखिम

- ऐसे संकेत उमर रहे हैं कि विनिर्माण कार्य और वैश्विक व्यापार में गिरावट अब थमने वाली है। इसके भारत के निर्यात पर सकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं। [जिससे निर्यात स्पर्धा क्षमता सुधरेगी]
- रियल एस्टेट क्षेत्र को बढ़ावा देने और इसके परिणामस्वरूप देश में निर्माण गतिविधि को बढ़ावा देने पर सरकार का आग्रह स्पष्ट है। गृहस्थीं द्वारा आवास में उच्चतर निवेश से अर्थव्यवस्था में अचल निवेश बढ़ेगा। मौजूदा अवििक्रित गृह भण्डार को बचा जा सकता है और अगर रियल एस्टेट डेवलपर्स घरों की कीमतें गिराने की अनुमति देकर “हेयर-कट” लेने को तैयार हों,

तो बैंक/गैर-बैंक दोनों ऋणदाताओं के की तुलना पत्र को शुद्ध किया जा सकता है।

- देश में निवल एफडीआई के मजबूत और बढ़ते प्रवाह के रूप में वैश्विक भावना भारत का पक्ष ले रही है। बढ़ते व्यापार तनाव के मद्देनजर अन्य देशों के निवेशकों का भारत में स्थानांतरण भी प्रवाह में इजाफा करेगा। एनआईपी की घोषणा भू-क्षेत्र और हरित क्षेत्र दोनों परियोजनाओं में देश में एफडीआई अंतर्वाह को और बढ़ाएगी। एफडीआई दिशानिर्देशों में निरंतर छूट विदेशी निवेशकों की चिंताओं को दूर करेगी और निवेश के माहौल में सुधार करेगी।
- मेंक इन इंडिया को बढ़ावा न केवल निर्यात को बढ़ावा देगा बल्कि उन उत्पादों के आयात को प्रतिस्थापित भी करेगा जिसमें भारत में घरेलू विनिर्माण की संभावना है।
- विश्व बैंक द्वारा लगभग 190 देशों के लिए मूल्यांकन किया गया जिसमें भारत व्यापार करने के अपने बैंक में लगातार सुधार कर रहा है। जीएसटी के क्रियान्वयन से इसके बैंक में सुधार से व्यापार सुगमता में प्रगति हुई है क्योंकि माल की सीमा पार आवाजाही में कम प्रतीक्षा समय लगता है। जैसे ही जीएसटी का कार्यान्वयन आगे बढ़ता है, घरेलू बाजार के बढ़ते एकीकरण से व्यावसायिक लागत कम होगी और नए निवेश की सुविधा होगी। भूमि और श्रम बाजार में लगातार सुधार से व्यावसायिक लागत में और कमी आएगी।
- नई विनिर्माण कंपनियों के लिए आधार कॉर्पोरेट कर की दर को घटाकर 15 प्रतिशत किया जाएगा जिससे पूंजी लागत की गिरावट दर से ऊपर निवेश के प्रतिफल दर में वृद्धि होगी और नए निवेश की वृद्धि में प्रोत्साहन मिलेगा।
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विलय से विलय की गई संस्थाओं की वित्तीय ताकत बढ़ेगी, जोखिम में कमी आएगी और परिणामस्वरूप ऋण दरों में कमी आएगी।

### 2020-21 में जीडीपी वृद्धि का अनुमान

1.58 ऐसी घटनाओं से होने वाले नकारात्मक जोखिम, जो अधिकतर काल्पनिक हैं और इस प्रकार, अमूर्त हैं। दूसरी ओर सकारात्मक जोखिम उन सुधारों में निहित हैं जो पहले से ही चल रहे हैं और इस तरह वास्तविकता के करीब हैं। निवल मूल्यांकन पर, यह प्रतीत होता है कि सकारात्मक जोखिम प्रबल होना चाहिए, खासकर जब शासन, एक मजबूत जनादेश के साथ है, सुधारों

पर शीघ्रता से कार्रवाई करने की क्षमता होगी। भारत की जीडीपी वृद्धि 2020-21 में दृढ़ता से पलटनी चाहिए और 2019-20 में 5 प्रतिशत की वृद्धि के निम्न सांख्यिकीय आधार पर तो और अधिक।

1.59 दोनों नकारात्मक/सकारात्मक जोखिमों के निवल मूल्यांकन पर, 2020-21 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर में 6.0 से 6.5 प्रतिशत की वास्तविक वृद्धि की उम्मीद है।

### अध्याय एक नजर में

- 2019 का साल, वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक अनिश्चितता से भरे वर्ष के रूप में उभरा है, जिसके दौरान विश्व उत्पादन वृद्धि, वर्ष-2019 के वैश्विक वित्तीय संकट से वर्ष 2017 के 38 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2018 से 3.6 प्रतिशत से घटते हुए 2.9 प्रतिशत की सबसे धीमी गति से बढ़ने का अनुमान है।
- वैश्विक विनिर्माण, व्यापार और मांग के लिए निराशावादी माहौल के बीच, भारतीय अर्थव्यवस्था ने 2019-20 की पहली छमाही में 4.8 प्रतिशत की मामूली वृद्धि के साथ उत्पादन में अनुमानित वृद्धि की तुलना में कम वृद्धि देखी है, जो वर्ष 2019-20 की दूसरी छमाही में 6.2 प्रतिशत से भी कम है।
- वास्तविक उपभोग की सुस्त वृद्धि से प्रेरित वास्तविक निश्चित निवेश में तेज गिरावट न जीडीपी वृद्धि में वर्ष 2018-19 की दूसरी छमाही से 2019-20 की पहली छमाही तक गिरावट दर्ज की है। हालांकि, 2019-20 की दूसरी तिमाही में, सरकार द्वारा अंतिम खपत में उल्लेखनीय वृद्धि की वजह से वास्तविक खपत में भी वृद्धि हुई है।
- आपूर्ति पक्ष पर, आमतौर पर जीवीए (जोड़ा गया सकल मूल्य) वृद्धि कम होने में सभी क्षेत्रों नामतः “कृषि और संबद्ध गतिविधियों” और “लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाओं” का योगदान रहा है, जिनकी वृद्धि दर वर्ष 2018-19 की दूसरी छमाही की तुलना में वर्ष 2019-20 की पहली छमाही के दौरान अधिक थी।
- भारत के बाहरी क्षेत्र ने 2019-20 की पहली छमाही में कुछ स्थिरता हासिल की है, जिसमें जीडीपी के प्रतिशत के तौर पर चालू खाता घाटा (सीएडी), वर्ष 2018-19 के 2.1 से घटकर वर्ष 2019-20 की पहली छमाही में 1.5 प्रतिशत हो गया है, प्रभावशाली विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) हुआ, पोर्टफोलियो प्रवाह का प्रतिक्षेप हुआ और विदेशी मुद्रा भंडार की अभिवृद्धि भी हुई है। वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही के दौरान कच्चे तेल की कीमतों में कमी की वजह से निर्यात की तुलना में आयात में अधिक तेजी से कमी आई है जो मुख्य रूप से चालू खाता घाटा (सीएडी) भी कम करता है।
- खाद्य मुद्रास्फीति में अस्थायी वृद्धि के बाद वर्ष 2019-20 की पहली छमाही में हेडलाइन मुद्रास्फीति पुनः 3.3 प्रतिशत से बढ़कर दिसंबर 2019-20 में 7.35 प्रतिशत हो गई जिसमें वर्ष के अंत तक गिरावट आने की उम्मीद है। वर्ष 2019-20 में कोर/स्थायी और डब्ल्यूपीआई (थोक मूल्य सूचकांक) मुद्रास्फीति में वृद्धि, मांग का दबाव बनाने का सुझाव देती है।
- जीडीपी वृद्धि में कमी को संवृद्धि चक्र के शिथिलन की रूप रेखा से समझा जा सकता है। वास्तविक क्षेत्र पर बाधा के रूप में वित्तीय क्षेत्र के कार्य से निदेश-संवृद्धि उपयोग में कमी आती है जैसा आर्थिक समीक्षा 2018-19 में भी कहा गया था।
- निवेश, खपत और निर्यात को बढ़ावा देने के प्रयास में, वर्ष 2019-20 में सरकार ने दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) के तहत दिवाला समाधान प्रक्रिया को तेज करने की दिशा में महत्वपूर्ण सुधार किए हैं, विशेष रूप से संकटग्रस्त रियल एस्टेट और एनबीएफसी क्षेत्र के लिए ऋण को आसान बनाना, और अन्य उपायों के बीच राष्ट्रीय इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन 2019-2025 की घोषणा की।
- वर्ष 2019-20 के लिए भारत की 5 प्रतिशत जीडीपी वृद्धि दर पर सीएसओ के पहले अग्रिम अनुमानों के आधार पर 2019-20 की द्वितीय छमाही में जीडीपी दर में इजाफा होने की उम्मीद है। एक मजबूत जनादेश वाली सरकार सुधारों पर तेजी से अमल करने और वर्ष 2020-21 में अर्थव्यवस्था में फिर से उछाल लाने की ओर अग्रसर है।

**REFERENCES**

International Monetary Fund. 2017. "Household Debt And Financial Stability", Chapter 2 in Global Financial Stability Report, October 2017: Is Growth at Risk. IMF

Mian, Atif. and Amir Sufi. 2018. "Finance and business cycles: the credit-driven household demand channel," *Journal of Economic Perspectives*, 32(3), 31-58.

Pandey, Radhika, Ila Patnaik, and Ajay Shah. 2018. "Measuring business cycle conditions in India." Working Papers 18/221, National Institute of Public Finance and Policy. [https://nipfp.org.in/media/medialibrary/2018/04/WP\\_221.pdf](https://nipfp.org.in/media/medialibrary/2018/04/WP_221.pdf)

"White Paper February 2019," Liases Foras, accessed January 10 2020, [https://www.liasesforas.com/admin/WhitePaper/36/WhitePaper\\_2019-05-02\\_63692396967411.pdf](https://www.liasesforas.com/admin/WhitePaper/36/WhitePaper_2019-05-02_63692396967411.pdf)

## परिशिष्ट

### नए सुधार

सरकार ने 2019-20 में अर्थव्यवस्था में सम्पूर्ण निवेश, उपभोग तथा निर्यात बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। इस इनमें से कुछ महत्वपूर्ण सुधार निम्नलिखित हैं:

#### निवेश बढ़ाने के लिए उपाय

- दिसम्बर, 2019 में, मंत्रिमंडल ने ऋणशोधन तथा दिवालियापन कोड (द्वितीय संशोधन) बिल, 2019 अनुमोदित किया। इस संशोधन का लक्ष्य है ऋणशोधन स्वीकृति प्रक्रिया में तेजी लाना तथा इसके अतिरिक्त व्यापार करने की सुगमता में सुधार करना।
- 31 दिसम्बर, 2019 को, सरकार ने 2019-20 से 2024-25 तक प्रत्येक वर्ष के लिए राष्ट्रीय अवसरचंका पाइपलाइन (एनआईपी) पर टास्क फोर्स की रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट ने प्रस्ताव प्रस्तुत किए जिनका सकल मूल्य लगभग 102 लाख करोड़ रु. है।
- आयकर अधिनियम 1961 तथा वित्त (स.2) अधिनियम 2019 में कुछ संशोधन करने के लिए सरकार कर-निधरण कानून (संशोधन) अध्यादेश 2019 में लाई है।
  - (i) 2019-20 के प्रभाव से आयकर अधिनियम में एक नया प्रावधान जोड़ा गया है जो किसी घरेलू कम्पनी को 22 प्रतिशत की दर पर आयकर भुगतान करने का विकल्प देता है। यदि वे कोई छूट/प्रलोभन का नहीं लें। इस कम्पनियों की प्रभावी कर दर जुर्माना तथा अधिकर को मिलाकर 25.17 प्रतिशत होगी। ऐसी कम्पनिया न्यूनतम विकल्पी कर के भुगतान के लिए भी बाध्य नहीं होंगी।
  - (ii) विनिर्माण में नये निवेश को आकर्षित करने के लिए तथा सरकार की 'भारत में बनाओं' पहल को प्रोत्साहित करने के लिए, 2019-20 के प्रभाव से आयकर अधिनियम में एक नया प्रावधान रखा गया है जो ऐसी किसी घरेलू कम्पनी को निगमित करता है अथवा 1 अक्टूबर 2019 के बाद विनिर्माण में नया निवेश करता है, उसे 15 प्रतिशत कर दर पर आयकर भुगतान करने का विकल्प देता है। यह लाभ उन कम्पनियों के लिए उपलब्ध है जो किसी प्रकार की छूट/प्रलोभन नहीं लेते हैं तथा 31 मार्च 2023 से पहले अपना उत्पादन प्रारंभ कर देती हैं। इन कम्पनियों के लिए प्रभावी कर दर जुर्माना तथा अधिकर को मिलाकर 17.01 प्रतिशत होगी। ऐसी कम्पनियां न्यूनतम विकल्पी कर का भुगतान करने के लिए भी बाध्य नहीं होंगी। भारत अब कारपोरेट टैक्स में विश्व में न्यूनतम दरों वाले देशों में शामिल हो गया है।
- तीव्र संवृद्धि के लिए तीव्र निवेश जरूरी है, जो साख की सुदृढ़ आपूर्ति पर निर्भर करता है। सरकार ने इस विषय में उल्लेखनीय कदम उठाए हैं।
  - (i) अर्थव्यवस्था में ऋण एवं निवेश को बढ़ावा देने के लिए 2019-20 के बजट में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पी.एस.बी.) में ₹ 70,000 करोड़ रुपए के नवीन पूंजी अंतः प्रवाह की घोषणा की। इस प्रावधान के अंतर्गत 2019 नवंबर तक ₹ 60,314 करोड़ का अंतः प्रवाह किया गया है, जिससे बैंकों का विकास एवं निवेश के लिए सज्जित किया गया है।
  - (ii) सुदृढ़ बैंक 5 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर की अर्थव्यवस्था हासिल करने के लिए अनिवार्य हैं। सशक्त राष्ट्रीय उपस्थिति एवं वैश्विक पहुंच वाले नई पीढ़ी के बैंकों की सृष्टि करने के लिए समेकन का प्रस्ताव रखा गया है। इस समेकन के कारण उत्पन्न होने वाले परिचालन दक्षता लाभ से उधार की लागत को कम करने की उम्मीद है।



- (iii) रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने फरवरी 2019 से अपना रुख कड़े से निष्पक्ष और जून 2019 से उदार बना दिया है। तदनुसार, 2019 फरवरी से नीति दर में 135 बीपीएस की कमी की गई है।
- (iv) आवास एवं आधारीक संरचना परियोजनाओं में ऋण वृद्धि के लिए प्रस्ताव रखा है। 1 अक्टूबर 2019 से बैंकों द्वारा सूक्ष्म और छोटे संगठनों को प्रदान
- (v) रिजर्व बैंक ने सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को बैंकों द्वारा किए गए सभी परिवर्तीदर ऋणों को एक अक्टूबर, 2019 से किसी निर्दिष्ट बाह्य कसौटी दरों से जोड़ने का निर्णय लिया है। इन कसौटी दरों में नीति रेपो दर, भारत सरकार की 3 या 6 महीने के राजकोषीय पक्षकों पर प्रतिप्राप्ति दर या फाइनेन्सियल वेचमार्क्स इन्डिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इंगित कोई अन्य दर हो सकती है।
- सरकार के ऑटो क्षेत्र की संवृद्धि को बढ़ाने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं:
  - (i) एक बारीय पंजीयन शुल्क जून, 2020 तक टाल दिया गया है।
  - (ii) पंजीयन की संपूर्ण अवधि के 31 मार्च 2020 तक खरीदे गए बीएस IV वाहन के लिए मान्य।
  - (iii) 31 मार्च 2020 की अवधि के दौरान खरीदे वाहनों पर 30 प्रतिशत तक की मूल्य हास दर अर्थात 15 प्रतिशत का अतिरिक्त मूल्य हास।
  - (iv) इलैक्ट्रिक वाहनों एवं आन्तरिक दहन वाहनों (आइसीबी) का पंजीकरण जारी रहेगा
  - (v) मांग बढ़ाने के लिए सरकारी विभागों द्वारा पुराने वाहनों के स्थान पर नए वाहन की खरीददारी बदलने पर लगे प्रतिबंध को हटाए जाएंगी।
- दिसंबर 2019 में एमएसएमई ब्याज आर्थिक सहायता योजना के आधुनिकीकरण को प्रचालन कठिनाइयों को आगे कम करने तथा कम लागत पर ऋण देने के लिए पहुंच को सुधारने हेतु अनुमोदित कर दिया गया था।
- सरकार ने केन्द्रीय सार्वजनिक उद्यमों निकायों (सीपीएसयू), केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसआई) केन्द्रीय सार्वजनिक वित्तीय संस्थान (सीपीएफआई), तथा अन्य सरकारी संगठनों के लिए वित्तपोषण के अतिरिक्त साधनों को सृजित करने हेतु भारत बांड एक्सचेंज ट्रेड फंड (ईटीएफ) के सृजन एवं शुरू करने को अनुमोदित किया। भारत बान्ड ईटीएफ देश में पहला कार्पोरेट बान्ड रहेगा
- स्थावर क्षेत्र को प्रोत्साहन देने तथा उपभोक्तों को घर खरीदने के लिए प्रोत्साहन देने के उद्देश्य सरकार ने प्रमुख उपाय किए हैं।
  - (i) सरकार ने 'सस्ते एवं मध्य आय' आवासन क्षेत्र में रूकी हुई आवासीय योजनाओं को पूर्ण करने के लिए प्राथमिक ऋण वित्तपोषण प्रदान करने हेतु एक विशेष विंडो की स्थापना का अनुमोदन किया है। वित्तपोषण के उद्देश्य के लिए सरकार प्रयोजन के रूप में कार्य करेगी तथा सरकार द्वारा अंतर्वाह किए जाने वाली कुल प्रतिबद्धता 10,000 करोड़ रु तक होगी। लगभग 25,000 करोड़ रु की कुल निधिको बनाने के लिए बैंक, एलआईसी तथा अन्यो से भी योगदान मांगा जा रहा है। वित्तपोषण को सेवी से पंजीकृत श्रेणी II एआईएफ (वैकल्पिक निवेश कोष) ऋण वित्तपोषण के रूप में स्थापित किया जाएगा तथा यह पेशेवर रूप से चलाया जाएगा।
  - (ii) प्रधानमंत्री आवास योजना के योग्य लाभार्थियों को इसके द्वितीय चरण (2019-20 से 2021-22) के दौरान शौचालय, विद्युत तथा एलपीजी कनेक्शन जैसी सुविधाओं के साथ 1.95 करोड़ घर प्रदान किया जाएंगे।

- (iii) भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से घर खरीददार जोकि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत योग्य हैं के वित्तपोषण को सुकर बनाने के लिए ईसीपी दिशानिर्देश नरम किए जाएंगे। यह सस्ते घरों हेतु के लिए विद्यमान शर्तों के अतिरिक्त हैं।
- (iv) गृह निर्माण अग्रिम: गृह निर्माण अग्रिम पर ब्याज दर कम कर दी गई है तथा इसे सरकारी प्रतिभूतियों के लाभ से जोड़ दिया गया है।
- (v) सस्ते घरों को प्रोत्साहित करने के लिए 45 लाख रु. तक के मूल्य वाले घरों की खरीदारी हेतु 31 मार्च, 2020 तक उठाए गए ऋणों पर चुकता ब्याज हेतु 1.5 लाख रु. तक का अतिरिक्त कटौती।
- (vi) बैंकों में ऋण उत्पादों से संबंधित रेपोरेट/बाह्य बैंच मार्क शुरू करना। ब्याज दरों को रेपोरेट से सीधे जोड़ने से गृह ऋण हेतु कम हुई ईएमआई।
- (vii) राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा 20,000 करोड़ रु की एचएफसी का प्रावधान जिससे यह 30,000 करोड़ हो गई है।
- किसी अस्थायी नकदी अथवा नकदी प्रवाह विसंगति के मामलों को सुलझाने के लिए एनबीएफसी आवासीय वित्त कंपनियां (एचएफसी) को गारंटी सहायता तथा समर्थ करने के लिए सरकार ने पीएसबी द्वारा वित्तीय रूप से अच्छी (एनबीएफसी) (एचएफसी) से उच्चतर पूर्व संपत्तियों की खरीदी हेतु 'आंशिक ऋण गारंटी योजना' शुरू की है। आर्थिक कार्य विभाग (डीए) द्वारा यथा सहमत, संपूर्ण गारंटी की राशि योजना अथवा 10,000 करोड़ रु. के अंतर्गत बैंकों द्वारा खरीदी जाने वाली संपत्तियों के उचित मूल्य के 10 प्रतिशत तक से जो भी कम हो को सीमित कर दिया है। योजना एनबीएफसी/एचएफसी को कवर करेंगी जोकि 1 अगस्त, 2018 के पूर्व एक वर्ष अवधि के दौरान एसएमए-0 श्रेणी में फिसल गया है, तथा परिसंपदा पूल बीबीबी + या अधिक रेटिंग के हैं।
- स्टेन्डअप इंडिया योजना को 2025 तक बढ़ा दिया गया है। यह योजना का उद्देश्य ऐसे ग्रीन फील्ड इंटरप्राइस स्थापित करने के लिए जिनमें कम से कम एक अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति उधारकर्ता तथा कम से कम एक महिला प्रति बैंक ब्रांच को 10 लाख से 100 लाख रु. के बीच बैंक ऋणों की सुविधा देना है। गैर-व्यक्तिक इंटरप्राइस के मामले में शेयर धारिता तथा नियंत्रित शेयर का कम से कम 51 प्रतिशत एससी/एसटी अथवा महिला उद्यमी द्वारा धारित किया जाना चाहिए।
- सरकार ने अधिकतर क्षेत्रों में स्वचालित मार्ग द्वारा 100 प्रतिशत तक एफडीआई अनुमति देने की नीति को उदार करते हुए एफडीआई नीति को निवेशक अनुकूल बनाया है।
- स्टार्टअप तथा उनके निवेश की असली कठिनाइयों को कम करने के लिए आयकर अधिनियम (एंजल कर से संबंधित) की धारा 56(2) (VIIB) डीपीआईआईटी से पंजीकृत स्टार्टअप के लिए अब लागू नहीं होगी।

### उपभोग बढ़ाने के उपाय

1.41 सरकार ने अर्थव्यवस्था में खर्च एवं उपभोग को बढ़ाने के लिए आय, विशेषकर ग्रामीण आय को बढ़ाने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं

- वर्ष 2019-20 सत्र के लिए सभी अधिदेशित रबी फसल खरीफ के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि।
- लघु एवं सीमांत किसानों को सुनिश्चित आय सहायता प्रदान करना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम किसान) योजना नकद अंतरण के जरिए 6000 प्रतिवर्ष की आय सहायता देकर (भूमि जोतों के आकार को

बिना विचार करते हुए) सभी योग्य किसान परिवारों तक विस्तारित की गई है।

- सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा को प्राप्त करने के लिए कदम के साथ सरकार ने एक नई योजना अनुमोदित की है जोकि व्यापारी समुदायों को पेंशन कवरेज प्रदान करती है। इस योजना के अंतर्गत सभी दुकानदारों, खुदरा व्यापारियों एवं स्वरोजगार व्यक्तियों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् 3 हजार रु. प्रति महीना की न्यूनतम मासिक पेंशन सुनिश्चित की गई है।
- 1 अगस्त, 2019 से सभी इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी दर 12 प्रतिशत से 5 प्रतिशत तक कम कर दी गई है तथा ईवी के लिए चार्जर अथवा चार्जिंग स्टेशन पर जीएसटी दर 18 प्रतिशत से 5 प्रतिशत तक कम कर दी है। स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा इलेक्ट्रिक (12 यात्रियों से अधिक की ले जाने वाले) वाहनों को किराये पर लेने में जीएसटी से छूट दी जाएगी

### निर्यात को सद्द करने के उपाय

- निर्यात उत्पादों (आरओडीटीईपी) पर शुल्कों या करों में निर्यात प्रोत्साहन के लिए करों और शुल्कों की प्रतिभूति के लिए सुधार की योजना भारत योजना से व्यापारिक निर्यात एमईआइएस की जगह ले लेगी। वस्त्र और सभी अन्य क्षेत्र जो वर्तमान एमईआइएस में 2 प्रतिशत तक का प्रोत्साहन प्राप्त कर रहे उनको आरओडीटीईपी में बदला जाएगा। जिसके प्रभाव से, आरओडीटीईपी पर्याप्त प्रोत्साहित निर्यातकों से वर्तमान सभी योजनाओं की तुलना में अधिक है।
- विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (संशोधित) विधेयक 2019 का अनुमोदन हो गया है जिसमें केन्द्र सरकार द्वारा अधि सूचित ट्रस्ट या इकाई को विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र की एक इकाई की स्थापना करने की पात्रता के लिए विचारा जाएगा।
- निर्यात क्षेत्र में ऋण को सद्द बनाने के लिए आरबीआई ने प्राथमिकता वाले क्षेत्र के अर्न्तगत ऋण नियमों की स्वीकृति सीमा को बढ़ाया है। इस सीमा को प्रति उधारकर्ता 25 करोड़ रुपये से 40 करोड़ रुपये तक बढ़ाया है। इससे आगे, वर्तमान मानदंड, जिसमें ऐसी इकाई जिसका टर्नओवर 100 करोड़ रुपये तक का हो, उसे हटा दिया गया है।
- ऋण निर्यात गारंटी निगम (इसीजीसी) ने निर्यात के लिए बैंकों को ऋण प्रदान करने की पूंजी में उच्चतर बीमा कवर देने के लिए निर्यात ऋण बीमा योजना (इसीआइसी) के प्रसार को बढ़ाएगा। यह निर्यात ऋण जिसमें ब्याज दर भी शामिल है, की संपूर्ण लागत को कम करेगा विशेषकर एमएसएमई में।
- सर्करा सत्र 2019-20 के दौरान अधिकतर स्टॉक की निकासी के लिए सरकार ने सर्करा निर्यात निति को मंजूरी दे दी है। सर्करा सत्र 2019-20 के लिए यह एक एकमुश्त निर्यात सब्सिडी 10,448 रुपये प्रति मेट्रिक टन (एमटी) की दर से सर्करा मिलों को उपलब्ध कराएगी। इस उद्देश्य के लिए कुल अनुमानित व्यय लगभग 6268 करोड़ रुपये उपगत होगा।
- हस्तकरघा उद्योग को निर्यात के लिए सक्षम बनाने हेतु प्रभावी गति देना, वस्त्र मंत्रालय के सहयोग से भारत वर्ष से कारीगरों का पंजीकरण प्रभावी होगा।